

अनुगामिनी

ईडी के नोटिस पर संजय राउत बोले- आओ गिरफ्तार कर लो **3** दूसरी टी20 में आयरलैंड को हराकर सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम **8**

एआईएफएफ चुनाव में भाइचुंग पराजित कहा- आगे भी बना रहूंगा फुटबॉल का सेवक

अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 02 सितम्बर । पूर्व भारतीय फुटबॉल गोलकीपर तथा पश्चिम बंगाल से भाजपा के विधायक कल्याण चौबे ने आज सम्पन्न हुए अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। उन्हें सर्वाधिक 33 वोट मिले हैं, जबकि पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान भाइचुंग भूटिया को केवल वोट से ही संतोष करना पड़ा।

इस सम्बंध में पूछे जाने पर भाइचुंग ने कहा कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पिछले दो दशकों से फुटबॉल का सेवक रहा हूँ और आगे भी रहूंगा। मैं समझ सकता हूँ कि इससे मेरे समर्थकों एवं शुभचिंतकों को बुरा लगा होगा, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरा समर्थन करने वाले हरेक व्यक्ति के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ। साथ ही भूटिया ने अपने समर्थकों को काफी

राजनीतिक दबाव के बावजूद मैदान में टिके रहने का भी श्रेय दिया। भाइचुंग ने आगे कहा कि मैं सिक्किम के साथ ही समूचे राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को स्वच्छ एवं गरिमामय स्थिति प्रदान करना चाहता हूँ और वादा करता हूँ कि इस दिशा में काम करता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि एक दिन फुटबॉल की अवश्य जीत होगी।

वहीं एआईएफएफ अध्यक्ष पद के चुनाव में भाइचुंग भूटिया की पराजय के बावजूद उनकी पार्टी हाम्रो सिक्किम पार्टी ने अपने कार्यकारी अध्यक्ष को सभी चुनौतियों के बावजूद मजबूती से लड़ाई लड़ने हेतु बधाई दी है। पार्टी के महासचिव बिराज अधिकारी ने कहा कि अत्यधिक राजनीतिक दबाव के कारण भले ही वे चुनाव हार गये हैं, लेकिन उनके प्रति सिक्किमवासियों ने जो प्यार और समर्थन दर्शाया है वह हृदय जीतने वाला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय



पार्टी (भाजपा) के काफी दबाव के बावजूद भूटिया ने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया है।

इसके साथ ही हाम्रो सिक्किम पार्टी ने समूचे राजनीतिक लॉबी तथा मेनला एथेन्या जैसे लोगों की तीव्र निंदा की जिन्होंने फुटबॉल खेल तथा इसकी बेहदती को फिक्सिंग से प्रभावित किया है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि अब एथेन्या को सिक्किम में फुटबॉल बेहदती हेतु हर वर्ष 40-50 लाख रुपये का फंड प्राप्त हो सकेगा।

सिक्किम कलाकार संघ का विवाद गहराया



अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 02 सितम्बर । सिक्किम कलाकार संघ के विवाद ने आज उस समय नया रूप ले लिया जब संघ की अस्थायी समिति के अध्यक्ष हरि हुंगेल ने आगामी 4 सितम्बर को होने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रम को अवैध करार देते हुए इसमें आमंत्रित लोगों से इसका बहिष्कार करने का आग्रह किया। उन्होंने यह कहते हुए कार्यक्रम के बहिष्कार की अपील की है कि जब कार्यक्रम आयोजन समिति ही अवैध है तब उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम एवं दिया जाने वाला सम्मान कैसे वैध हो सकता है। हुंगेल ने बताया कि 2018 में ही संघ की पूर्व कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

हरि हुंगेल ने स्थापना दिवस समारोह के बहिष्कार की अपील की

उसके बाद संगठन के आजीवन सदस्यों ने जब भी पत्राचार कर समिति के पुनर्गठन की मांग की है, तब उसे टाल दिया गया। इसलिए बाध्य होकर अब कानून का रास्ता अखिराया किया गया है।

आज यहां आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में हुंगेल ने कहा कि संघ की कार्यकारिणी समिति को कानूनी नोटिस मिलने के बाद उन लोगों ने अवैध रूप से स्थापना दिवस का आयोजन करने एवं करीब 60 लोगों सम्मानित करने का भी निर्णय लिया है। यह आयोजन और दिया जाने वाला सम्मान मान्य नहीं है। साथ ही उन्होंने नैतिक एवं आर्थिक

अनियमितता के आरोपों से घिरे सिक्किम कलाकार संघ से ऐसा आयोजन नहीं करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि 2018 से ही संघ ने अपना कोई आर्थिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन एवं कार्यकारिणी समिति की वैधानिकता सम्बंधी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। साथ ही हुंगेल ने सिक्किम के कलाकारों के कल्याण एवं नवोदित कलाकारों को अवसर प्रदान करने हेतु गठित कलाकार संघ की इस कार्यकारिणी पर इसे एक कम्पनी का रूप देकर आर्थिक अनियमितता का आरोप लगाया।

मत्स्य महोत्सव को पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

अनुगामिनी नि.सं.
पाकिम, 02 सितम्बर । प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) तथा इसके अवयवों के साथ ही मत्स्य महोत्सव को लेकर गंगटोक मत्स्य निदेशालय द्वारा आज पाकिम जिलान्तर्गत उत्तर रेगु में एक जागरूकता कार्यक्रम सह बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के वित्तपोषण में मत्स्य निदेशालय द्वारा चलाई जा रही किसानों के हित में विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही मत्स्य उत्पादन के बढ़ावे तथा पहले ग्रामीण मत्स्य महोत्सव के आयोजन की तैयारियों पर चर्चा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। इस अवसर पर मत्स्य निदेशालय के निदेशक एन जसवंत के अलावा अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र भंडारी, एडी लाहांग लिम्बू, पाकिम एडी श्रीमती गौरी मुखिया, रंगपो



आरओ केपी शर्मा, पंचायत अध्यक्ष एसके राई के अलावा अन्य अधिकारी एवं 60 मत्स्य पालक किसान उपस्थित रहे। यहां अपने वक्तव्य में एन जसवंत ने मत्स्य पालकों को रेगु में ट्राउट रेसवे में भागीदारी करने के साथ ही ग्रामीण फिश ईको-टूरिज्म पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रेगु में पर्यटन के दृष्टिकोण से फिश ईको-टूरिज्म की भी काफी सम्भावनाएं हैं। उल्लेखनीय है कि सिक्किम में पहली बार मत्स्य निदेशालय के

तत्वावधान में ग्रामीण मत्स्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्बंध में आज की बैठक में समितियों एवं उप-समितियों पर निर्णय लिया गया। वहीं आज कार्यक्रम के दौरान लुजाचेन के किसानों को एन जसवंत और पाकिम एडी श्रीमती गौरी मुखिया ने सम्मानित किया। इसके अलावा इस दौरान सम्बंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा पीएमएमएसवाई, गुप दुर्बटना बीमा, एफएफपीओ तथा आरएएस पर जानकारी भी प्रदान की गयी। वहीं यहां एक चर्चा सत्र भी हुआ।

वेदांत शर्मा व यश राज राई को प्रतिष्ठित नर बहादुर भंडारी फेलोशिप

अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 02 सितम्बर । सिक्किम के दो छात्रों को एक करोड़ रुपये वाली प्रतिष्ठित नर बहादुर भंडारी फेलोशिप योजना (एनबीबीएफएस) के लिए चुना गया है। गंगटोक निवासी 23 वर्षीय वेदांत शर्मा अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जाएंगे, वहीं नामची के 26 वर्षीय यशराज राई ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज लंदन में अपनी पढ़ाई करेंगे।

आईआईटी-बॉम्बे के 23 वर्षीय एयरोस्पेस इंजीनियर, वेदांत शर्मा ने अमेरिका में प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स में मास्टर्स करने के लिए 50 लाख रुपये की फेलोशिप हासिल की। सिन्धु निवासी शर्मा ने कहा कि मैंने 20 अगस्त को अपने दीक्षांत

समारोह के साथ इस साल अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। मुझे हमेशा एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी, और आईआईटी बॉम्बे में इसकी शिक्षा लेना खासा। उन्होंने कहा कि एयरोस्पेस में परास्नातक करना काफी महंगा है। लेकिन इसमें सरकार मेरी मदद करेगी। मैंने 6 अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भी कोशिश की थी, मुझे एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजिल्स (यूसीएल), जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिशिगन विश्वविद्यालय, पड़रू विश्वविद्यालय, इलिनोइस विश्वविद्यालय सहित अन्य सभी को अस्वीकार करना पड़ा। शर्मा ने आईआईटी-बॉम्बे के बाद भारत में नौकरी हासिल कर ली थी, वे नासा में नौकरी करना उनका सपना है।

शर्मा ने कहा कि नासा हमेशा से मेरी प्रेरणा रहा है, लेकिन नागरिकता एक मुद्दा है क्योंकि वे अमेरिकी नागरिकों की तलाश में हैं। भारत में, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे आवेदन हैं। मैंने जो क्षेत्र चुना है वह कृषि क्षेत्र और यहां तक कि पर्यटन में व्यापक प्रौद्योगिकी जरूरतों को शामिल करता है, जहां एयरोस्पेस सहायता कर सकता है। अंतरिक्ष और वैमानिकी में भारत की बढ़ती रुचि ने उन्हें आशान्वित रखा है क्योंकि शर्मा 26 सितंबर से अपनी आइवी लीग शिक्षा के लिए तत्पर हैं। इसी तरह, 26 वर्षीय नामची निवासी यश राज राई ने अपने परास्नातक को आगे बढ़ाने के लिए 50 लाख रुपये की फेलोशिप हासिल की है। वे इंपीरियल कॉलेज लंदन में वित्तीय प्रौद्योगिकी की



वेदांत शर्मा यश राज राई

पढ़ाई करेंगे। राई ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से पास आउट किया और दो महीने के लिए बेंगलूर में जेपी मॉर्गन चैस एंड कंपनी के साथ

इंटरशिप की। सिक्किम के पूर्व विधायक भोज राज राई के बेटे यश राज से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका, क्योंकि वह पहले ही लंदन पहुंच चुके हैं।

भाइचुंग के पराजय के लिए बीजेपी को दोष देना गलत : डॉ. राजू गिरी

अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 02 सितम्बर । ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष पद हेतु आज हुए चुनाव में भाजपा के पश्चिम बंगाल के नेता कल्याण चौबे विजयी हुए हैं। वहीं भाजपा की सिक्किम प्रदेश इकाई ने इस चुनाव को ऐतिहासिक करार दिया है।

पार्टी प्रवक्ता डॉ. राजू गिरी ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि देश के इतिहास में एआईएफएफ के इस चुनाव में पहली बार दो पूर्व फुटबॉल खिलाड़ियों ने प्रतिद्वन्द्विता की। वहीं यह भी पहली बार है कि कोई पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी एआईएफएफ का अध्यक्ष बना है। पार्टी ने विजयी हुए कल्याण चौबे को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके नेतृत्व में देश में फुटबॉल का विकास होने की उम्मीद जतायी है। वहीं उन्होंने भाइचुंग की पराजय को लेकर भाजपा को दोषी ठहराये जाने की भी निंदा की है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इस बार एआईएफएफ चुनाव में भाइचुंग भूटिया की उम्मीदवारी के कारण हमारे राज्य सिक्किम भी चर्चा के केंद्र में रहा। भाजपा सिक्किम

‘इस बार का एआईएफएफ चुनाव ऐतिहासिक’

इकाई ने भी अपनी ओर से भारतीय स्टार फुटबॉलर तथा सिक्किम के सपूत भाइचुंग भूटिया को समर्थन देने की अपील की थी। हालांकि उनके आशानुरूप चुनाव परिणाम न होने के बावजूद भूटिया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ इसमें प्रतिद्वन्द्विता की है। हमें उम्मीद है कि वे आने वाले समय में भी अपने स्तर से भारतीय फुटबॉल की बेहदती हेतु कार्य करेंगे।

वहीं भाजपा प्रदेश इकाई ने इस चुनाव को राजनीति के चरम से देखने वालों की खिचाई भी की है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि एआईएफएफ एक अराजक संगठन है और इसके अध्यक्ष पद पर चुनाव में राजनीतिक करने वाले असल में अपना चरित्र की उजागर कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस चुनाव में भाइचुंग की पराजय के लिए कुछ लोगों द्वारा भाजपा को दोषी ठहराये जाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद के



चुनाव में विजयी हुए कल्याण चौबे पश्चिम बंगाल से हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है।

वहीं इस चुनाव में देश के 34 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के फुटबॉल संघों ने मतदान किया है। यदि इसमें राजनीति होती तो कल्याण चौबे को 34 में 33 वोट नहीं मिलते। पश्चिम बंगाल, केरल जैसे घोर भाजपा विरोधी राज्यों से भी कल्याण चौबे को वोट दिये जाने का मतलब यही है कि इस चुनाव में निष्पक्षता के साथ राजनीति से ऊपर उठ कर मतदान हुआ है।

गिरी ने आगे कहा कि खेल जगत के मामलों में इस प्रकार की राजनीतिक टीका-टिप्पणी का हम तीव्र विरोध कर रहे हैं।

एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न



अनुगामिनी नि.सं.
गेजिंग, 02 सितम्बर । जिला बाल संरक्षण इकाई, गेजिंग ने सारदोंग माध्यमिक विद्यालय में एक दिवसीय जागरूकता सह संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता नोडल अधिकारी एससीपीसीआर रोशनी गुरुंग ने की।

उप. एसपी अभियोजन सावित्री प्रधान, डीसीपीओ गेजिंग सह सोरेंग मिस भावना सुब्बा, लामा गांव प्रधान के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, स्कूल के प्रभारी अध्यापन एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, जिला बाल संरक्षण अधिकारी गेजिंग और सोरेंग जिला भावना सुब्बा ने पोक्सो संशोधन अधिनियम 2019, जिले में बाल अधिकार,

संरक्षण और सेवा संरचना और विभिन्न बाल संबंधित कानूनों पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों से दुर्व्यवहार और तस्करी के खिलाफ एक क्लब बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि एटीएसए क्लब के गठन का मुख्य उद्देश्य हमारे बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना और बाल शोषण और तस्करी के खतरनाक मुद्दों का मुकाबला करना है। इसी के अनुरूप एटीएसए क्लब का गठन किया गया।

इस बीच, एससीपीसीआर नोडल अधिकारी सह डीसीपीओ दक्षिण रोशनी गुरुंग ने किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, साइबर अपराध, बाल तस्करी और विभिन्न अन्य बाल संबंधित कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम में डिप्टी एसपी प्रॉसिक््यूशन सावित्री प्रधान आत्मरक्षा पर प्रदर्शन किया।

मतदाता सूची निर्माण के लिए प्रशिक्षण सम्पन्न



अनुगामिनी का.सं.
पाकिम, 02 सितम्बर । आगामी पंचायत चुनावों से पहले मतदाता सूची के मसौदा प्रारूप को लेकर दावों एवं शिकायतों के निपटारे हेतु आज पाकिम कम्प्यूनिटी कॉम्प्लेक्स में सभी एसडीएम, बीडीओ तथा बीएलओ के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गंगटोक के एडीएम हेमंत राई यहां रिसेंसर्स पर्सन के रूप में शामिल हुए। इस दौरान पाकिम जिला

कलेक्टर द्वारा मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार लिंकिंग की प्रगति की जानकारी ली गयी तथा साथ ही उन्होंने सभी ईआरओ एवं ईआरओ को चुनाव आयोग की तय समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने हेतु निगरानी का निर्देश दिया। वहीं इस अवसर पर आगामी 18 सितम्बर, रविवार को मतदाता पहचान पत्र से आधार को जोड़ने हेतु एक विशेष अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया।

एटीएमए शासी समिति व बोर्ड गठन के लिए बैठक सम्पन्न

अनुगामिनी नि.सं.
सोरेंग, 02 सितम्बर । कृषि तकनीक प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के लिए एक जिलास्तरीय शासी समिति तथा बोर्ड गठन हेतु सोरेंग जिला कलेक्टर भीम ठटाल ने आज यहां अपने सभागार में एक बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर संयुक्त कृषि निदेशक प्रणय गुरुंग, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के संयुक्त सचिव



रॉ. किशोर थापा, संयुक्त सहकारिता रजिस्ट्रार पीडी भूटिया, उप बागवानी निदेशक डीपी शर्मा के अलावा कृषि एवं उद्योग विभाग के प्रतिनिधियों एवं लाभान्वितों ने भी शिरकत की। बैठक में जिलास्तर पर एजेंसी के प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डाला गया। बैठक की शुरुआत प्रणय गुरुंग द्वारा योजना के सम्बंध में दी गयी संक्षिप्त परिचय से हुई जिसमें उन्होंने इसे खास तौर पर जिले के प्रगतिशील किसानों के कल्याण हेतु पहल बताया। वहीं अपने संबोधन में डीसी सह एटीएमए चेयरपर्सन

ने कहा कि लाभान्वित किसानों को इस योजना से अवगत होना चाहिए। साथ ही उन्होंने 'फार्मर्स फ्रेंडली' की इस अवधारणा के तहत खास कर युवा किसानों को प्रोत्साहन देने की बात कही। वहीं उन्होंने स्थानीय किसानों की बेहदती हेतु बाजार नियामक गठित करने पर भी जोर दिया। इस सम्बंध में उन्होंने किसानों से विभाग के साथ समन्वय रख कर अपनी उत्पादित फसलों को बेचने को कहा। इस दौरान नवगठित समिति के गठन पर बधाई देते हुए ठटाल ने

2025 में राज्य के भारतीय गणराज्य में शामिल होने की स्वर्ण जयंती उपलक्ष्य पर एक रोड मैप तैयार करने की सलाह दी। वहीं इस अवसर पर संयुक्त कृषि अधिकारी मनीष प्रधान द्वारा कमिटी के मुख्य उद्देश्यों के साथ ही एटीएमए की गतिविधियों पर एक प्रस्तुति भी दी गयी। इसके अलावा इस अवसर पर किसानों की शिकायतों एवं समस्याओं के समाधान हेतु एक खुली चर्चा भी आयोजित हुई। वहीं इस दौरान किसानों से फसल बीमा का लाभ उठाने को भी कहा गया।

अब दिखते ही हवालात में होंगे बाँबी कटारिया, दिल्ली पुलिस ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर



नई दिल्ली, 02 सितम्बर (एजेन्सी)। विवादास्पद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बलविंदर कटारिया उर्फ बाँबी कटारिया दिखते ही हवालात के अंदर होंगे। पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। बाँबी को जनवरी में स्पाइसजेट की फ्लाइट में कथित तौर पर सिगरेट पीते देखा गया था। इसके बाद से ही वह फरार चल रहे हैं।

अगस्त में एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह फ्लाइट के दौरान सिगरेट पीते नजर आ रहे थे। यह वायरल वीडियो जनवरी महीने का बताया जा रहा है।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमारी टीमों ने हाल ही में उनके एक ठिकाने पर छापा मारा था, लेकिन वह वहाँ नहीं मिले। अब उनके

खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। हम उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे।

वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए कहा था कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दिल्ली पुलिस को स्पाइसजेट के मैनेजर जसबीर सिंह से शिकायत मिली थी और सेप्टी और सिक्योरिटी उपायों के उद्देश्य के लिए नागरिक उड्डयन अधिनियम 1982 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

यह भी आरोप है कि बाँबी कटारिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से तस्वीरें और वीडियो अपलोड किए थे, जहां उन्हें 21 जनवरी को स्पाइस जेट की उड़ान

संख्या -706 में लाइटर के साथ सिगरेट पीते हुए देखा गया था।

वहीं, उत्तराखंड में सड़क के बीच कथित तौर पर शराब पीने के आरोप में भी कटारिया के खिलाफ देहरादून के कैंट थाने में एक और मामला दर्ज किया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून में सड़क पर टेबल लगाकर कथित तौर पर शराब पीने के मामले में फरार यूट्यूबर बाँबी कटारिया पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि देहरादून पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट हासिल कर लिया है। उत्तराखंड पुलिस ने कटारिया को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम स्थित उनके घर पर भी छापा मारा, लेकिन वह लगातार फरार हैं। इसके बाद आरोपी बाँबी कटारिया पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत हुई मंजूर



नई दिल्ली, 02 सितम्बर (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें 2002 के दंगों के मामलों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज तैयार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति एस. रविवर्धन और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने कहा कि चूंकि आवश्यक हिरासत में पूछताछ पूरी हो गई है, इसलिए अंतरिम जमानत के मामले पर सुनवाई होनी चाहिए थी, और कहा कि उनकी जमानत याचिका अभी भी गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

पीठ ने कहा, 'हम तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत देते हैं। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से उसकी जमानत याचिका पर फैसला करने को कहा, लेकिन इस बीच सीतलवाड़ अंतरिम जमानत पर बाहर हो जाएगी। अंतरिम जमानत का कोई आदेश पारित नहीं करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका पर लंबे समय तक स्थगन दिए जाने के बाद

उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सीतलवाड़ को निचली अदालत में अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का भी निर्देश दिया और यह स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय उसके आदेश से प्रभावित हुए बिना उसकी नियमित जमानत याचिका पर फैसला करेगा।

सुनवाई के दौरान, गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि सीतलवाड़ के साथ असाधारण व्यवहार करके बहुत बुरी मिसाल न बनाएं, जब उच्च न्यायालय पहले से ही मामले को देख रही है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह 25 जून से हिरासत में है और जांच तंत्र को सात दिनों की हिरासत में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत का फायदा मिला।

गुरुवार को, सुप्रीम कोर्ट ने चिता व्यक्त की थी कि गुजरात उच्च न्यायालय ने सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर, छह सप्ताह के लिए वापसी योग्य नोटिस जारी किया और गुजरात सरकार से उन मामलों का विवरण लाने को कहा, जहां एक महिला से जुड़े मामले में, हाईकोर्ट ने इतना लंबा स्थगन दिया।

नए पीएमओ के निर्माण के लिए मिली पर्यावाणीय मंजूरी

नई दिल्ली, 02 सितम्बर (एजेन्सी)। सेंट्रल विस्था परियोजना के हिस्से के रूप में एंजोक्वैटिव एन्क्लेव के निर्माण को दिल्ली प्रदेश पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) ने मंजूरी दे दी है। इस एन्क्लेव में प्रधानमंत्री का नया कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय का निर्माण किया जाएगा।

दिल्ली प्रदेश विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) ने पिछले सप्ताह एसईआईएए को परियोजना को पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने की सिफारिश की थी। एसईआईएए ने बुधवार को एक बैठक में परियोजना पर चर्चा की तथा इसे मंजूरी दे दी।

वन विभाग ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को 23 अगस्त को दिल्ली पेड़ संरक्षण कानून, 1994 के तहत सेंट्रल विस्था परियोजना स्थल से 807 में से 487 पेड़ों को उखाड़कर कहीं और लगाने की मंजूरी दी थी।

बैठक में एसईआईएए ने कहा कि इस परियोजना से निर्माण स्थल पर 60 प्रतिशत पेड़ों को हटया जाएगा।

सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कहा कि इस प्रस्ताव को गत वर्ष दिसंबर में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए भेजा गया था।

परियोजनाओं को मंजूरी के लिए एसईआईएए के पास भेजे जाने से पहले उनका मूल्यांकन करने वाली एसईएसी ने इस महीने की शुरुआत में पेड़ों को उखाड़कर कहीं और लगाने के लिए दिल्ली सरकार की नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक उप-समिति का गठन किया था।

सरकार ने दिसंबर 2020 में अधिसूचित की गई नीति में कहा था कि संबंधित एजेंसियों को उनके विकास कार्यों के कारण प्रभावित 80 प्रतिशत पेड़ों को किसी और स्थान पर लगाना होगा।

एसईएसी ने पहली बार 31 जनवरी को एक बैठक में प्रस्ताव पर गौर किया था और उसने निर्माण स्थल पर से बड़ी संख्या में पेड़ों के हटाने की सीपीडब्ल्यूडी की योजना पर चिंता जताई थी।

बाद में, सीपीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव को संशोधित किया और प्रतिरोपित किए जाने वाले पेड़ों की संख्या 630 से घटकर 487 कर दी और निर्माण स्थल पर छोड़े जाने वाले पेड़ों की संख्या 154 से बढ़ाकर 320 कर दी। नौ अप्रैल को हुई बैठक में, एसईएसी ने पर्यावरण मंजूरी के लिए एसईआईएए को संशोधित प्रस्ताव की सिफारिश करने का फैसला किया।

एसईआईएए ने हालांकि, मामले को एसईएसी को वापस भेज दिया। 1,381 करोड़ रुपये की परियोजना के संशोधित प्रस्ताव के अनुसार, सीपीडब्ल्यूडी निर्माण स्थल पर 1,022 पेड़ों का रखरखाव करेगा, ताकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति 80 वर्ग मीटर भूखंड क्षेत्र में एक पेड़ होना चाहिए।

बढ़ती आबादी देश की जनसंख्या नियंत्रण पर

नई दिल्ली, 02 सितम्बर (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह याचिका कोर्ट में अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव दांडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती द्वारा दायर की गई। जितेंद्रानंद सरस्वती ने 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या ही देश की आधी परेशानियों के लिए जिम्मेदार है।

जस्टिस केएम जोसेफ और

हृषिकेश रॉय की पीठ ने सरकार से जवाब मांगा और मामले को इसी तरह की लंबित याचिकाओं के साथ टैग किया। सरस्वती द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि हर साल जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। याचिका में कहा गया है कि जब बेरोजगारी और गरीबी, खाद्य आपूर्ति की सीमा, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं आदि में भारी बढ़ोत्तरी होती है। याचिका में अधिक जनसंख्या की समस्या के कारण भारत के लाखों नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी नियम, विनियम और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए केंद्र सरकार

से गाइडलाइन मांगी है।

याचिका में सरकार को हर महीने के पहले रविवार को स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित करने के लिए कहा गया है। ताकि ईडब्ल्यूएस और बीपीएल परिवारों को पोलियो टीके के साथ अधिक जनसंख्या के बारे में जागरूकता फैलाने, टीके, गर्भनिरोधक गोलियां, कंडोम आदि का वितरण हो सके। साथ ही भारत के विधि आयोग को तीन महीने के भीतर जनसंख्या नियंत्रण उपायों पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने और प्रतिवादी (सरकार) को उचित विचार के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दे। याचिकाकर्ता ने कहा कि हर व्यक्ति को स्वच्छ हवा, पीने के पानी, स्वास्थ्य



सुविधा, रहने, आजीविका चलाने और शिक्षा का अधिकार जैसी बुनियादी मौलिक अधिकार संविधान के तहत गारंटीकृत हैं।

वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1.39 बिलियन के करीब है जो विश्व की लगभग 17.8 प्रतिशत जनसंख्या

है, लेकिन भारत के पास विश्व की केवल 2 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि और केवल 4 प्रतिशत पेंशन है। याचिका में दावा किया गया है कि अमेरिका में हर दिन 10,000 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि भारत में हर दिन 70,000 बच्चे पैदा होते हैं।

केंद्र सरकार बोली- आईएस कैडर नियमों में बदलाव पर अभी कोई फैसला नहीं, राज्यों से मांगा इनपुट

नई दिल्ली, 02 सितम्बर (एजेन्सी)। केंद्र सरकार ने कहा कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा नियमों में प्रस्तावित बदलावों पर विभिन्न पक्षकारों से मिली सूचनाओं पर गौर कर रही है और अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है। इनमें नौकरशाहों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से संबंधित मामलों पर राज्य के अधिकारों को कम करने का प्रस्ताव है। मौजूदा नियमों में आईएसएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा परस्पर विचार विमर्श की अनुमति मिली हुई है।

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में राज्यों से मिले पत्रों की प्रतियां साझा करने से इनकार कर दिया। उसने विश्वासपूर्ण संबंधों के कारण ऐसी सूचना के खुलासे से छूट देने वाले पारितोषिका कानून के एक प्रावधान का हवाला देते हुए राज्य के जवाबों पर उठाए गए कदमों की जानकारी भी साझा करने से इनकार कर दिया।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने पिछले साल दिसंबर में भारतीय

प्रशासनिक सेवा (काडर) नियमों, 1954 में बदलावों का प्रस्ताव दिया था, जिससे राज्यों से अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की मांग करने वाले केंद्र के अनुरोध को टुकराने की शक्तियां छीन ली जाएंगी। उसने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से इस पर टिप्पणीय मांगी थीं। विभाग ने अर्जी पर अपने जवाब में कहा, विभिन्न राज्य काडर/संयुक्त काडर तथा अन्य पक्षकारों से प्रस्ताव पर मिली टिप्पणीय/सूचनाएं अभी विचाराधीन हैं और भारत सरकार ने अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।' उसने 29 अगस्त को दिए जवाब में कहा, इसके मद्देनजर, जो सूचना मांगी गयी है वह विश्वासपूर्ण संबंध पर आधारित है और सूचना का अधिकार कानून, 2005 की धारा 8(1) की शर्तों के तहत इसके खुलासे से छूट मिली हुई है।'

विभाग के अधिकारियों ने कहा कि केंद्र में संयुक्त सचिव स्तर तक आईएसएस अधिकारियों के घटते प्रतिनिधित्व की प्रवृत्ति देखी गयी है क्योंकि ज्यादातर राज्य केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे हैं तथा केंद्र में

उनके द्वारा प्रायोजित अधिकारियों की संख्या बहुत कम है।' गौतमलब है कि आईएसएस अधिकारियों को एक काडर आवंटित किया जाता है जो कोई राज्य या राज्यों का एक समूह या केंद्र शासित प्रदेश होता है। प्रत्येक काडर को सीडीआर की अनुमति दी जाती है ताकि अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम करने का अवसर मिले, जिससे उनका अनुभव बढ़ता है।

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने फरवरी में संसद को बताया था कि राज्य केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को नहीं भेज रहे हैं और इसके कारण सेवा नियमों में बदलाव करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम नौ राज्यों ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान ने प्रस्तावित संशोधनों पर आपत्ति जतायी है। उन्होंने बताया कि ऐसी जानकारी है कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश ने अपनी सहमति दे दी है।

खर्च बढ़ने से रेलवे बोर्ड चिंतित, विभिन्न भत्तों पर होने वाले व्यय को काबू में लाने को कहा

नई दिल्ली, 02 सितम्बर (एजेन्सी)। परिचालन खर्च बढ़ने से चिंतित रेलवे बोर्ड ने सातों जोन से ओवरटाइम, रात्रिकालीन ड्यूटी और यात्रा तथा ईंधन एवं रखरखाव के लिये मिलने वाले भत्तों की समीक्षा करने को कहा है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी के त्रिपाठी ने तिमाही समीक्षा बैठक में पाया कि परिचालन से जुड़े खर्च काफी अधिक हैं। चालू वित्त वर्ष में मई तक सातों जोन में यह रेलवे के पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 26 प्रतिशत औसत वृद्धि से कहीं ऊपर चला गया है।

ये जोन हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (37.9 प्रतिशत), उत्तर रेलवे (35.3 प्रतिशत), दक्षिण-मध्य रेलवे (34.8 प्रतिशत), दक्षिण-पश्चिम रेलवे (33.1 प्रतिशत), उत्तर-पश्चिम रेलवे (29 प्रतिशत), पश्चिम रेलवे (28 प्रतिशत) और उत्तर-मध्य रेलवे (27.3 प्रतिशत)। एक सवाल के जवाब में रेलवे ने कहा कि परिचालन खर्च को लेकर 2022-23 के लिये कुल बजटीय अनुमान 2.32 लाख करोड़ रुपये



है। चूंकि खातों का ऑडिट होना बाकी है, संबंधित आंकड़े अस्थायी हैं। विभाग ने कहा, रेलवे ने वित्त मंत्रालय के व्यय नियंत्रण और प्रबंधन पर दिये गये दिशानिर्देश को जारी किया है।

विभिन्न मोर्चों पर मितव्ययिता और किफायती उपायों को लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, ईंधन की खपत को अनुकूलतम बनाने के साथ माल भंडार प्रबंधन में सुधार पर भी ध्यान दिया जा रहा है।' सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान रेलवे बोर्ड ने जोन को अपने खर्च को कम करने के लिये तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया और महाप्रबंधकों को इस संदर्भ में कार्ययोजना बनाने को कहा। उसने

कहा, ओवरटाइम, रात्रि ड्यूटी भत्ता, किलोमीटर भत्ता जैसे खर्चों को नियंत्रित किया जा सकता है।

इसपर नजर रखे जाने की जरूरत है।' इसके अलावा, पूर्व रेलवे (ईआर), दक्षिणी रेलवे (एसआर), पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) और उत्तर रेलवे (एनआर) जैसे जोन को किलोमीटर भत्ते को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यह भत्ता ट्रेन को संचालित करने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है। वहीं दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर), पूर्व-मध्य रेलवे (ईसीआर) और पूर्व तटीय रेलवे (ईसीओआर) को रात्रि ड्यूटी भत्ते पर अपने खर्च को कम करने के लिये कहा गया है।

स्टार सीमेंट ने इंजीनियर्स मीट का आयोजन किया

गंगटोक, 02 सितम्बर। स्टार सीमेंट ने गंगटोक में 'कनेक्ट, कोलाबोरेट एंड सेलैब्रेट' थीम के साथ एक इंजीनियर्स मीट का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न इंजीनियरों के बीच विचारों और संबंधों के आदान-प्रदान के उद्देश्य से गंगटोक के सिनक्लेयर्स होटल में इंजीनियर्स मीट का आयोजन किया गया था। श्री शौचिक चक्रवर्ती, एवीपी-सेल्स एंड मार्केटिंग, स्टार सीमेंट ने सभी इंजीनियरों को एक

प्रेजेंटेशन दिया और उन्हें स्टार सीमेंट के कॉर्पोरेट प्रोफाइल से अवगत कराया गया।

इंजीनियरों को सीमेंट कंपनी की निर्माण प्रक्रिया और उसके गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में बताया गया। विभिन्न प्रकार के निर्माण में सीमेंट की भूमिका और विभिन्न आधुनिक निर्माण प्रथाओं को शिखर सम्मेलन में उपस्थित इंजीनियरों को समझाया गया। समिट में भाग लेने वाले इंजीनियरों में बिल्डिंग एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट (पीडब्ल्यूडी), सेंट्रल

पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट (सीपीडब्ल्यूडी) और अन्य अधिकारियों जैसे विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे। इंजीनियर्स मीट पर टिप्पणी करते हुए, श्री ज्योति स्वर्ूप अग्रवाल, चीफ मार्केटिंग अफिसर ने कहा, इंजीनियर इतिहास का निर्माता रहा है, और है। वे हर महान निर्माण के पीछे असली प्रेरणा हैं और उनके अपार योगदान को स्वीकार करना और उनके प्रति अपना सम्मान दिखाना हमारा कर्तव्य है।

मैक्समटेक डिजिटल वेंचर्स के साथ वी गेम्स की साझेदारी

सिलीगुड़ी, 02 सितम्बर। वी गेम्स ने अपने गेमिंग पार्टनर मैक्समटेक डिजिटल वेंचर्स के साथ तीन अद्वितीय मोड में मल्टीप्लेयर और प्रतिस्पर्धी गेम लॉन्च किए हैं। वीआई ने इस मल्टीप्लेयर और कम्प्यूटेटिव गेमिंग कंटेंट को वी ऐप पर वी गेम्स की छत्रछाया में लॉन्च किया है। मैक्समटेक डिजिटल वेंचर्स के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया, वी गेम्स अब 40+ लोकप्रिय, कम्प्यूटेटिव और अत्यधिक कुशल मल्टीप्लेयर गेम जैसे एक्सप्रेस लुडो, क्विज मास्टर, सॉलितेरिय किंग, गोल्टन गोल और क्रिकेट लीग प्रदान करती है। वी गेम्स पर मल्टीप्लेयर गेमिंग के लिए भागीदारी के अवसर का विस्तार करते हुए, वी ने गैर-वी उपयोगकर्ताओं के लिए भी सेवा का विस्तार किया है। एक वी उपयोगकर्ता किसी को भी आमंत्रित कर सकता है, चाहे वे वी उपयोगकर्ता हों या गैर-वी

उपयोगकर्ता, उनके साथ खेलने के लिए।

इस पहल पर टिप्पणी करते हुए, वोडाफोन आइडिया के चीफ मार्केटिंग अफिसर, अवनीश खोसला ने कहा, हमने कुछ महीने पहले वी गेम्स लॉन्च किए थे और अब हम अपनी पेशकश को सोशल या मल्टीप्लेयर गेमिंग तक बढ़ा रहे हैं जो वी को स्थापित करने के हमारे उद्देश्य की दिशा में एक स्वाभाविक प्रगति है।

केजुअल और सीरियस गेमर्स दोनों के लिए पसंदीदा जगह है। उपयोगकर्ता रिवाइंड कोइन्स कमा सकते हैं और कोइन्स को रिडीम या तो अधिक गेम खले सकते हैं, बड़े टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं या रोमांचक उपहार प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता वी ऐप (https://bit.ly/3B4bFXw) पर वी गेम्स का उपयोग कर सकते हैं। उपयोगकर्ता गूगल प्ले स्टोर या ऐपल स्टोर से वी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।

‘भ्रष्टों को बचाने के लिए राजनीति में हो रहा नया ध्रुवीकरण’, पीएम मोदी के आरोपों पर नीतीश कुमार का पलटवार

पटना, 02 सितम्बर (का.सं.)। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल युनाइटेड नेता नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी पर पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने राजनीति में ध्रुवीकरण की बात कही थी। पटना में पत्रकारों के सवाल पर सीएम नीतीश ने पीएम मोदी के बयान पर हंसी उड़ाई और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने वाजपेयी का शासन काल में केंद्र की सरकार में काफी काम किया था और आज बिहार में बहुत काम कर रहे हैं।



उनके चेहरे पर हंसी थी।

नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'राजनीति में ध्रुवीकरण' के दावों का भी खंडन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, 'भ्रष्टों को कोई नहीं बचा रहा है। उन्हें (भाजपा को) सोचना चाहिए कि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है।

पीएम मोदी ने आज देश के पहले भारत में निर्मित विमानवाहक पोत (आईएनएस विक्रान्त) को नौसेना को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने तीखा हमला बोला। कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर सरकार में कोई कुछ कहता है, तो मैं ध्यान नहीं देता हूँ। इस दौरान

नीतीश की पीएम पद की दावेदारी को लेकर जदयू की 'पोस्टर रणनीति'

पटना, 02 सितम्बर (का.सं.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक भले ही खुद को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं किया हो, लेकिन जनता दल युनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के सामने जिस तरह पोस्टर लगाए गए हैं, उससे साफ है कि जदयू ने नीतीश कुमार को पीएम पद की दावेदारी साबित करने की तैयारी कर ली है।

वैसे, यह कोई पहली बार नहीं है कि जदयू की ओर से नीतीश कुमार के राष्ट्रीय स्तर पर छवि बनाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले भी नीतीश को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लायक नेता बताकर जदयू के नेता उनके राष्ट्रीय स्तर पर छवि बनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली।

भाजपा से अलग होकर जिस तरह से नीतीश कुमार ने पाला बदल कर महागठबंधन के साथ हुए, तभी यह क्यास लगने लगे थे, कि नीतीश प्रधानमंत्री बनने के लिए भाजपा का साथ छोड़ा है।

अब इसकी गवाही राजधानी पटना में लगे पोस्टर भी दे रहे हैं। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में नए पोस्टर लगे। इन पोस्टरों में सिर्फ तस्वीर के नाम पर नीतीश कुमार की तस्वीर है।

पोस्टरों में लिखे वाक्य साफ संकेत दे रहे हैं नीतीश की पार्टी जहां नीतीश कुमार की छवि राष्ट्रीय स्तर पर बनाना चाहती है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साध रहे हैं।

अलग-अलग, बड़े-बड़े पोस्टरों में 'जुमला नहीं हकीकत', 'मन की नहीं काम की', 'प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा', 'आगाज हुआ बदलाव होगा' जैसे कई दावे लिखे गए हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी बिहार आए थे। राव के संवाददाता सम्मेलन में भी नीतीश के पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछा गया। इसके बाद तो नीतीश खुद कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गए, लेकिन राव ने भी साफ कुछ नहीं बोल पाए।

नीतीश कुमार को पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाने वाले जदयू कार्यालय में लगाए गए नए पोस्टर पर जब जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने पीएम पद की दावेदारी को स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 से अभी तक जो भी वादे किए वे पूरे नहीं हुए। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने बिहार में 17 वर्षों तक शासन किया, कोई जुमला नहीं चलाया, जो वादा उन्होंने किया उसे पूरा किया।

सरकार कब तक जुमले बांटेगी? बेरोजगारों पर आई रिपोर्ट पर प्रियंका गांधी का हमला

नई दिल्ली, 02 सितम्बर (एजेन्सी)। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड़ा गांधी ने केंद्र सरकार पर बेरोजगारी के कारण आत्महत्या से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि के बारे में हालिया रिपोर्टों पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर 'जुमले' देने और युवाओं की हताशा का कोई वास्तविक जवाब नहीं देने का भी आरोप लगाया।

कांग्रेस महासचिव ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि बेरोजगारी दर 45 वर्षों में सबसे अधिक है। कांग्रेस महासचिव ने लिखा, वर्ष 2021 में देश में बेरोजगारी के कारण 11,724 लोगों की आत्महत्या से मौत हुई। यह संख्या साल 2020 के मुकाबले 26 फीसदी ज्यादा है। भाजपा सरकार में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी युवाओं को निराश कर रही है।

वाड़ा ने लिखा कि सरकार के पास 'इस भयानक बेरोजगारी' का न तो कोई इलाज है और न ही कोई जवाब। सरकार कब तक जुमले

बांटेगी (झूठे वादे)? उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले आठ वर्षों में, नौकरी चाहने वालों में से प्रत्येक 1,000 में से केवल तीन को ही रोजगार मिला है।

गौर हो कि बढ़ती बेरोजगारी और आसमान छूती महंगाई के आरोप में केंद्र सरकार विपक्षी दलों की गर्मी का सामना कर रही है। इससे पहले दिन में, कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा था कि भाजपा 'अनजान' है और केवल 'अर्थव्यवस्था के रीसेट के लिए रोडमैप तैयार करने के बजाय विपक्षी सरकारों के रीसेट पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

बता दें कि भारत में बेरोजगारी दर अगस्त महीने में बढ़कर 8.28 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई में 6.80 प्रतिशत थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने ग्रामीण बेरोजगारी 7.68 प्रतिशत थी, जबकि शहरी बेरोजगारी दर 7.68 प्रतिशत थी।

सीबीआई-ईडी से बीजेपी के नेताओं को कौन बचा रहा : तेजस्वी यादव

पटना, 02 सितम्बर (का.सं.)। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राज्य में सीबीआई और ईडी के द्वारा कई कार्रवाई की गई। इसमें राजद नेताओं खासकर तेजस्वी यादव और उनके करीबियों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर राजद के नेताओं ने सवाल उठाए और बिहार में बगैर परमिशन के सीबीआई-ईडी की इंटी पर रोक लगाने की मांग की गई। इसे लेकर अंदरखाने में सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश की गयी।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान पर राजद नेता और राज्य के डिफ्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने पूछा कि बीजेपी के लोग दूध के धुले हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के 1000 से ज्यादा विधायक हैं और 300 से ज्यादा सांसद हैं। लेकिन, उनमें से किसी के ठिकानों पर छाप नहीं पड़ रहा। तेजस्वी यादव ने पूछा कि अगर उनके यहां छाप नहीं पड़ रहा है तो उन्हें कौन बचा रहा है? जो बीजेपी में चले जाते हैं वे दूध से धुल जाते हैं।

दरअसल पटना में पत्रकारों ने



प्रधानमंत्री के उस बयान को लेकर सवाल किया जिसमें पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के बचाने के लिए देश में नया राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है। भ्रष्ट लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार ने कार्रवाई शुरू हुई तो कुछ राजनीतिक समूह भ्रष्टाचार का आरोप का सामना कर रहे लोगों को बचाने के लिए एक गुट में संगठित हो रहे हैं। इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सवाल मेरे लायक नहीं है। केंद्र में बैठे लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। इस बीच उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसदों और विधायकों को कोई-न-कोई तो बचा रहा है।

इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार किया। नीतीश कुमार ने कहा कि कौन क्या बोलता है इसपर पे ध्यान नहीं देते। पटना में पत्रकारों के सवाल पर सीएम नीतीश ने पीएम मोदी के बयान पर हंसी उड़ाई और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय

अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने वाजपेयी का शासन काल में केंद्र की सरकार में काफी काम किया था और आज बिहार में बहुत काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'राजनीति में ध्रुवीकरण' के दावों का भी खंडन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, 'भ्रष्टों को कोई नहीं बचा रहा है। उन्हें (भाजपा को) सोचना चाहिए कि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत (आईएनएस विक्रान्त) को नौसेना को समर्पित किया। कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई ने राष्ट्रीय राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण किया है। कुछ लोग खुले तौर पर आरोपों का सामना करने वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

बांग्लादेशियों ने झारखंड के पांच जिलों में बदल दी है डेमोग्राफी, मोहब्बत-निकाह और धर्मांतरण के हैं कई मामले

रांची, 02 सितम्बर (एजेन्सी)। बांग्लादेश की सीमा से करीब स्थित झारखंड के पांच जिलों की डेमोग्राफी तेजी से बदली है। पिछले तीन दशकों में बांग्लादेश से लाखों की तादाद में घुसपैठिए साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा जिलों के अलग-अलग इलाकों में आकर बस गये हैं। इन इलाकों में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर सरकारी विभागों ने केंद्र और राज्य सरकारों को समय-समय पर कई बार रिपोर्ट मिली है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 1994 में साहिबगंज जिले में 17 हजार से अधिक बांग्लादेशियों की पहचान हुई थी। इन बांग्लादेशियों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे, मगर इन्हें वापस नहीं भेजा जा सका। वर्ष 2018 में झारखंड की पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में गृह विभाग ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से इलाके की बदली हुई डेमोग्राफी के मद्देनजर पूरे राज्य में एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजनशिप) लागू कराने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। इसपर केंद्र की ओर से कोई निर्णय नहीं हो पाया था।

विधानसभा के बीते बजट सत्र के दौरान राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कार्यस्थान सूचना के जरिए संथाल परगना के जिलों में

बेटी को अवैध तरीके से टेका देने के लिए सक्सेना को बर्खास्त करें पीएम : आप

नई दिल्ली, 02 सितम्बर (एजेन्सी)। आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईएस) के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और एक खादी लाउंज की आंतरिक साजसज्जा (इंटीरियर डिजाइनिंग) का ठेका अपनी बेटी को दिया था।

आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल सक्सेना को बर्खास्त करने की मांग की। आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह भी मांग की कि कानून

जिले के गांवा थाना क्षेत्र की पुलिस ने पिहरा-चटनयादाह गांव से मोहम्मद नोशाद नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि उसने बांग्लादेश और भारत दोनों देशों की नागरिकता हासिल कर रखी थी।

खुफिया एजेंसियों ने भी समय-समय पर सरकारों को ऐसी रिपोर्ट भेजी है, जिनमें बांग्लादेशियों के घुसपैठ के तौर-तरीकों के बारे में विस्तृत व्योरा दर्ज है। गृह विभाग को भेजी ऐसी ही एक रिपोर्ट में बताया गया है कि संथाल परगना के साहिबगंज व पाकुड़ में चिह्नित अवैध प्रवासियों ने वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तक बनवाए हैं। इन इलाकों में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश व पापुलर फ्रंट आफ इंडिया और अंसार उल बांग्ला जैसे प्रतिबंधित संगठनों की पकड़ बढ़ रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि बांग्लादेश से आये लोगों ने स्थानीय महिलाओं से शादी कर ली और यहीं बस गये।

दुमका के अंकिता हत्याकांड के बाद ऐसे कई मामले उजागर हो रहे हैं। मसलन, दुमका की सानी डंगाल मोहल्ला की रहने वाली एक युवती के मुताबिक उससे एक लड़के ने अपने धर्म की पहचान छिपाकर दोस्ती की, खरार का वास्ता दिया और फिर शादी के बाद उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर दिया। उसके सामने इसके अलावा



तरीके से टेका देने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

सिंह ने कहा कि आप अपने विरष्ट वर्गीयों के साथ विचार-विमर्श कर रही है और मामले में अदालत का रुख करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा, दिल्ली के

यूपी के तर्ज पर बिहार में भी हो मदरसों का सर्वे : गिरिराज सिंह



पटना, 02 सितम्बर (का.सं.)। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में मदरसों और मस्जिदों का सर्वे कराने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी मदरसों और मस्जिदों की जांच होनी जरूरी है।

अपने बयानों से सुखियों में रहने वाले भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में भी खासकर सीमावर्ती इलाकों में भी यूपी की तर्ज पर मदरसों और मस्जिदों के सर्वे की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि बिहार की सीमा जो नेपाल से जुड़ा हो, बांग्लादेश की सीमा हो या बंगाल से जुड़ी सीमा हो सभी जगह मदरसों और मस्जिदों की जांच होनी चाहिए।

इस बात की जांच होनी चाहिए कि इन मदरसों और मस्जिदों में कौन लोग रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। रहने वाले लोग भारत के खिलाफ हैं या भारत के पक्ष में हैं।

उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मदरसों का सर्वे कराने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि मदरसों के सर्वे से कुछ लोगों खासकर ओवैसी जैसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन, उनके पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मुसलमानों को अच्छी शिक्षा मिले।

उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे लोगों को डर है कि कहीं ये न पता चल जाए कि कौन बांग्लादेशी है और कौन रोहिया हैं।

NAGALAND STATE LOTTERIES	
Draw Time: 08:00 PM	
DEAR VULTURE EVENING	
FRIDAY WEEKLY LOTTERY	
Draw No:192 DrawDate on:02/09/22	
1st Prize ₹ 1 Crore/- 44K 23368	
<small>(Unlucky Draw Prize Not)</small>	
Cons. Prize ₹1000/-	23368 (REMAINING ALL SERIALS)
	2nd Prize ₹ 9000/-
07152 10558 22639 40752 62824 66761 70362 83771 90968 95510	3rd Prize ₹ 450/-
	4th Prize ₹ 250/-
2203 2583 3812 4098 5106 5198 5928 6829 8449 9907	5th Prize ₹ 120/-
0338 1011 1418 2550 5571 5946 6551 7098 7394 8342	
0343 0369 0471 0510 0577 0759 0842 1183 1376 1414	
1651 1808 1872 2020 2057 2242 2254 2267 2500 2809	
2856 2865 3015 3169 3182 3281 3326 3372 3379 3511	
3561 3592 3652 3689 3722 3769 3970 4491 4630 4797	
4847 4851 4892 5008 5233 5278 5304 5389 5394 5530	
5646 5672 5823 5908 6006 6073 6077 6110 6301 6340	
6391 6585 6606 6730 6749 7104 7183 7238 7241 7336	
7425 7509 7602 7667 7673 7768 7803 7842 7851 8002	
8008 8042 8110 8266 8413 8479 8624 8685 8733 9021	
9045 9287 9313 9399 9436 9529 9734 9742 9756 9798	
ISSUED BY : THE DIRECTOR	
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND	
For Results, Please Visit : www.Nagalandlotteries.com	
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE	

NAGALAND STATE LOTTERIES	
Draw Time: 08:00 PM	
DEAR VULTURE EVENING	
FRIDAY WEEKLY LOTTERY	
Draw No:192 DrawDate on:02/09/22	
1st Prize ₹ 1 Crore/- 44K 23368	
<small>(Unlucky Draw Prize Not)</small>	
Cons. Prize ₹1000/-	23368 (REMAINING ALL SERIALS)
	2nd Prize ₹ 9000/-
07152 10558 22639 40752 62824 66761 70362 83771 90968 95510	3rd Prize ₹ 450/-
	4th Prize ₹ 250/-
2203 2583 3812 4098 5106 5198 5928 6829 8449 9907	5th Prize ₹ 120/-
0338 1011 1418 2550 5571 5946 6551 7098 7394 8342	
0343 0369 0471 0510 0577 0759 0842 1183 1376 1414	
1651 1808 1872 2020 2057 2242 2254 2267 2500 2809	
2856 2865 3015 3169 3182 3281 3326 3372 3379 3511	
3561 3592 3652 3689 3722 3769 3970 4491 4630 4797	
4847 4851 4892 5008 5233 5278 5304 5389 5394 5530	
5646 5672 5823 5908 6006 6073 6077 6110 6301 6340	
6391 6585 6606 6730 6749 7104 7183 7238 7241 7336	
7425 7509 7602 7667 7673 7768 7803 7842 7851 8002	
8008 8042 8110 8266 8413 8479 8624 8685 8733 9021	
9045 9287 9313 9399 9436 9529 9734 9742 9756 9798	
ISSUED BY : THE DIRECTOR	
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND	
For Results, Please Visit : www.Nagalandlotteries.com	
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE	

NAGALAND STATE LOTTERIES	
Draw Time: 06:00 PM	
DEAR EARTH FRIDAY	
WEEKLY LOTTERY	
Draw No:92 DrawDate on:02/09/22	
1st Prize ₹ 1 Crore/- 93L 36156	
<small>(Unlucky Draw Prize Not)</small>	
Cons. Prize ₹1000/-	36156 (REMAINING ALL SERIALS)
	2nd Prize ₹ 9000/-
03964 06656 12024 12171 16084 17949 64260 65460 80756 91909	3rd Prize ₹ 450/-
	4th Prize ₹ 250/-
0871 1177 1187 1451 2190 3555 4149 6819 7024 8885	5th Prize ₹ 120/-
0433 1667 1745 2458 3573 7962 8358 8625 8800 9199	
0161 0166 0173 0228 0234 0419 0469 0530 0612 0620	
0684 0758 0800 0960 1000 1023 1130 1205 1267 1303	
1605 1665 1670 1761 1881 1923 2009 2252 2639 2746	
2963 2975 2978 3130 3146 3163 3257 3351 3509 3530	
3549 3670 3730 3973 4122 4523 4598 4746 4810 5046	
5134 5269 5369 5411 5485 5599 5667 5669 5771 5824	
5872 5874 5984 6207 6225 6393 6451 6771 6815 6842	
6884 6926 6939 7045 7298 7316 7369 7457 7556 7591	
7909 7913 7938 8186 8276 8331 8595 8686 8715 8764	
8833 9062 9107 9187 9449 9519 9542 9564 9908 9972	
ISSUED BY : THE DIRECTOR	
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND	
For Results, Please Visit : www.Nagalandlotteries.com	
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE	

कर्मचारी राज्य बीमा निगम	
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत	
पंचदीप भवन, 5/1, ग्रांट लेन, कोलकाता 700012	
फोन: 033 2236 4451 - 56, ई-मेल: rd-westbengal@esic.nic.in	
वेबसाइट: www.esic.nic.in	
कार्यालय स्थान के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति	
अतिरिक्त आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक, ईएसआईसी परिचय बंगाल एवं सिक्किम क्षेत्र, गैरिज (परिचय सिक्किम) एवं गैरिज (उत्तर सिक्किम) में ईएसआईसी शाखा कार्यालय की स्थापना के लिए, पट्टे पर, निर्मित आकृति स्थान को विराया पर देने वाले व्यक्ति, पाठियों से (ईओआई) अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करते हैं।	
उक्त स्थापना के लिए केवल प्रथम तल अथवा भूमि तल पर सुविधाजनक स्थान पर अनुमानित 1000 वर्गफुट क्षेत्र की आवश्यकता है।	
ईओआई को मुखबंध लिफाफा में एवं अतिरिक्त आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक, ईएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय, सामान्य शाखा, 5/1, ग्रांट लेन, कोलकाता-700012 के पते पर भेजना है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया www.esic.nic.in देखें।	
ईओआई के बना करने की अंतिम तिथि विज्ञापन प्रकारान की तिथि से 21 दिन है।	
ह./.	
एसी एवं आरडी, ईएसआईसी प.ब., एवं सिक्किम क्षेत्र	

सेना में महिला शक्ति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश में बना पहला विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रान्त नौसेना को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिला शक्ति को नौसेना की शक्ति के साथ सांकेतिक तौर पर मिलाते हुए कहा कि आईएनएस विक्रान्त जब हमारे समुद्री इलाके की रक्षा करने उतरेगा तो उस पर महिला सैनिक भी होंगी। उनके शब्दों में, सागर की निस्सीम शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति अब नए भारत की पहचान होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नौसेना ने सभी ब्रांच महिलाओं के लिए खोलने का फैसला कर लिया है। यह बड़ी घोषणा इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ समय से किए गए अथक प्रयासों के बावजूद भारतीय सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

ध्यान रहे, आर्मी और एयरफोर्स के मुकाबले नेवी में महिलाओं की मौजूदगी अच्छी है, लेकिन वहां भी यह महज 6.5 फीसदी है। प्रसंगवश एयरफोर्स में महिलाओं का प्रतिशत 1.08 फीसदी है और आर्मी में महज 0.56 फीसदी। बेशक सशस्त्र सेनाओं को दुनिया भर में पुरुषों का क्षेत्र माना जाता रहा है, लेकिन इसमें महिलाओं की संख्या हर जगह इतनी कम नहीं है। उदाहरण के लिए, 2020 में यूएस मिलिटरी अकैडमी में 23 फीसदी कैडेट महिलाएं थीं। भारत में सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की कम संख्या की एक वजह शायद यह है कि यहां नर्सिंग जैसी शाखाओं को छोड़ दें तो महिलाओं को प्रवेश भी देर से मिला। लेकिन यह बात भी सही है कि वहां उनकी भूमिकाएं भी सीमित ही रहीं।

होना तो यह चाहिए था कि उन्हें नई-नई भूमिकाओं में खुद को आजमाने और कठिन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता, लेकिन कई मामलों में इसका उलटा देखने को मिला। हालांकि इसके पीछे किसी तरह की दुर्भावना के बजाय समाज की पितृसत्तात्मक सोच और महिलाओं की सुरक्षा की चिंता का ही ज्यादा रोल रहा, लेकिन फिर भी यह सचाई है कि सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं ने जो उपलब्धियां अपने नाम दर्ज की हैं और जिस तरह से अपने लिए स्पेस क्रिएट करती जा रही हैं उसका सबसे ज्यादा श्रेय पुरुष वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पहली और दूसरी पीढ़ी की महिलाओं को और देश की न्यायपालिका को जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर दखल देकर महिलाओं के लिए यहां लेवल ख्रलेइंग फील्ड सुनिश्चित करने की कोशिश की है। हालांकि अब भी महिलाओं को आर्मी में कॉम्बैट रोल नहीं दिया जा रहा, लेकिन पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बदौलत प्रतिष्ठित नैशनल डिफेंस अकैडमी की प्रवेश परीक्षा में बैठने की इजाजत पा लेने के बाद अब महिलाएं सेना के विभिन्न मोर्चों पर खुद को साबित करने में पीछे नहीं रहेंगी। ऐसे में प्रधानमंत्री की ताजा घोषणा न केवल सशस्त्र सेनाओं के अंदर सेवा दे रही महिलाओं को बल्कि इसका सपना देख रही लड़कियों को भी ताकत देगी।

संवादकीय पृष्ठ

उच्च शिक्षण संस्थानों का साथ लीजिए

बद्री नारायण
भारत विकसित होने की राह पर है। अभी हाल में प्रधानमंत्री ने आने वाले पचीस वर्षों में भारत को विकसित देश बनाने का नारा भी दिया है। भारत में इस वक्त दुनिया के किसी भी विकसित देश से कई गुना ज्यादा विकास परियोजनाएं चल रही हैं। गरीबों की जीवन शक्ति, विकास की चाह रखने वालों में क्षमता निर्माण, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, महिला शक्ति निर्माण, सामाजिक संयोजन, आर्थिक समाहितकरण की अनेक योजनाएं भारत सरकार संचालित कर रही है। साथ ही, जलशक्ति, गतिशक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी आंतरिक सुरक्षा, ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक परियोजनाएं केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन सभी परियोजनाओं का लक्ष्य भारत को विकासमान महाशक्ति बनाना तो है ही, साथ ही इनसे भारत में विकास का महाआख्यान गढ़ने की कोशिश भी है, जो देश में विकासवात्मक हस्तक्षेप और विकास की आकांक्षा व प्रेरणा विकसित कर सके।

लेकिन विडंबना यह है कि विकास के इस अभियान के ईद-गिद अभी ज्ञान निर्माण का कार्य नहीं हो सका है। भारतीय राज्य खुद ही अभियान चला रहा है और अभियान को लागू होते हुए खुद ही देख रहा है। इसमें एक तीसरे पक्ष की जरूरत है। वह पक्ष हमारे देश के उच्च शिक्षा संस्थान हो सकते हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों और इनसे होने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव का आकलन कर सकते हैं। वे हमारी विकास प्रक्रिया के उपयोगी दस्तावेजोत्पन्न की अंजाम

दे सकते हैं।

जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में 1,000 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 416 राज्य विश्वविद्यालय, 125 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 361 निजी विश्वविद्यालय, 159 राष्ट्रीय महत्व के शोध संस्थान, जिनमें अनेक आईआईटी व आईआईएम शामिल हैं। ये सभी देश के विभिन्न भागों में फैले हैं। वन क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थल, सामूहिक क्षेत्र, हर जगह कोई न कोई उच्च शिक्षा का संस्थान है। इनके साथ कॉलेजों को जोड़ दिया जाए, तो संख्या लाखों तक जा सकती है। उच्च शिक्षा के ये संस्थान भारत में विकास की तीसरी आंख बन सकते हैं, जो निरपेक्ष होकर विकास की इस गति को देख सके और उसकी समुचित व्याख्या कर सके।

दुनिया के अनेक देशों में विश्वविद्यालय अपने-अपने मुलक में विकास के थिक टैंक के रूप में सक्रिय हैं। दुनिया में ऐसे अनेक विश्वविद्यालय हैं, जो अपने समाज और देश में विकासपरक हस्तक्षेप के कारण हो रहे सामाजिक बदलावों के आर्काइव और डाय केंद्र के रूप के सक्रिय तो हैं ही, साथ ही, अपने-अपने समाज में विकास के प्रकाश स्तंभ और विचार केंद्र के रूप में भी कार्यरत हैं।

भारत में उच्च शिक्षा संस्थान मूलतः शिक्षा व डिग्री देने के केंद्र के रूप में कार्यरत हैं। यह ठीक है कि इस प्रक्रिया में वे ऐसे छात्र पैदा करते हैं, जो विकास के इस अभियान में मानवीय शक्ति व एजेंसी के रूप में कार्य कर सकें, किंतु इससे भी आगे बढ़कर इन्हें भारत में विकास के विचार केंद्र के रूप में भी विकसित होने की अपेक्षा की जानी चाहिए। भारत में

उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने वजूद में यह एक नया आयाम शामिल करने की जरूरत अभी बाकी है। हमारे उच्च शिक्षा संस्थान विकास के विचार केंद्र एवं तीसरी आंख बन सकें, यह हमारे समय की एक बड़ी जरूरत है।

विकास के प्रयास सिर्फ आर्थिक-प्रशासनिक क्रिया ही नहीं, वरन एक विचार, दर्शन व विवेक के बड़े फ्रेम की भी मांग करते हैं। यह कार्य कोई राजसत्ता अकेले नहीं कर सकती। अभी तक बिना बौद्धिक विचार एवं आकलन के विकास का महायज्ञ किसी भी राष्ट्र में सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो सका है। भारत जब आज विकसित राष्ट्र बनने की जदोजहद की रहा है, तब भारतीय विश्वविद्यालय इस प्रक्रिया के मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकते। उन्हें विकास का न सिर्फ अध्ययन करना होगा, बल्कि विकास में हस्तक्षेप सहयोग भी करना होगा। जिन देशों में तेज आर्थिक विकास हुआ है, उनमें विश्वविद्यालयों की भूमिका व्यापक है। आज हम जहां भी हैं, वहां राज्य या सरकार सक्रिय है। उसकी सक्रियता कई रूपों में है। उनमें एक है - विकास परियोजनाओं का संचालन व उनसे बन रहा लाभार्थी समुदाय। हम जहां भी हैं, वहां के हमारे आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में कुछ न कुछ

बदल रहा है। हमारे दैनिक जीवन में हो रहे इन बदलावों का दस्तावेजोत्पन्न और उन पर गहन शोध की जरूरत है। यह कार्य राजसत्ता अकेले नहीं कर सकती, इसके लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को साथ लेना होगा। शायद इसकी जरूरत आज महसूस की जाने लगी है। भारत सरकार का शिक्षा विभाग देश के कई बड़े विश्वविद्यालयों,

आईआईटी एवं आईआईएम का एक संयुक्त पुल तैयार कर रहा है, जो देश के विकास के प्रयासों का नीतिगत आकलन तो करेगा ही, उनके सामाजिक प्रभावों का भी अध्ययन करेगा। साथ ही, ये केंद्रीय महत्व के शिक्षा संस्थान भारत सरकार के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर अपने को विकास के थिक टैंक के रूप में स्थापित कर सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर भारत में विकास दृष्टि, उनका आकलन और उनके सामाजिक प्रभावों पर अध्ययन करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। इसे जान की विरासत निर्माण के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।

सचमुच विकास ढांचागत संरचना ही निर्मित नहीं करता, वरन बौद्धिक संपदा भी सृजित करता है, किंतु यह बौद्धिक संपदा अभी तक प्रायः असंकलित, अपरिभाषित ही है। हो सकता है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की यह पहल एक ऐसी बौद्धिक संपदा सृजित करे, जो भविष्य में हमें सार्थक परिणाम दे।

ऐसी ज्ञान परंपरा राष्ट्र निर्माण की शक्ति भी देगी। इसके लिए जरूरी है कि हमारे देश में उच्च शिक्षा संस्थान सक्रिय होकर आगे आएँ और विकास में अपनी भूमिका बढ़ाएं। अभी तक कुछ उच्च शिक्षा संस्थानों के समाज विज्ञान व विकास अध्ययन विभाग इस दिशा में सक्रिय हैं। जरूरत है कि जो उच्च शिक्षा संस्थान जहां भी स्थित हैं, वहां की जिम्मेदारी लें, बदलावों का उपयोगी लेखा-जोखा रखें और अन्य संस्थानों के साथ साझा करें। बेशक, ये संस्थान अगर तीसरी आंख बन गए, तो देश विकास के पथ से जरा भी नहीं भटकेंगे।

ऋण जाल में पहुंचाने के लिए सब जिम्मेदार

एच डी देवेगौड़ा
अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1991-92 के बजट प्रस्तावों पर आम चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस बजट को गरीब विरोधी, किसान विरोधी, विकास विरोधी और मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाला मानता हूँ। मैंने कभी भी ऐसे बजट की आशा उस व्यक्ति (मनमोहन सिंह) से नहीं की थी, जो आर्थिक प्रबंध के क्षेत्र में बुद्धिमान, अनुभवी और वित्त विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। व्यापार बढ़ाने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कुछ कदमों की मैं सराहना करता हूँ। निर्यात बढ़ाने के लिए हमारी औद्योगिक और व्यापार नीतियों में परिवर्तन लाने के लिए कार्यवाही की गई, लेकिन कुल मिलाकर इस बजट का तात्पर्य यही है कि यह पूरी तरह किसानों, गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों का विरोधी है और साथ ही, विकास कार्यों के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई गई है, जहां तक इसके लिए प्रावधान का संबंध है, बजट में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इन बजट प्रस्तावों पर सरसरी तौर पर टिप्पणियां करते हुए मैं आपका ध्यान वित्त

मंत्री के भाषण के पहले पैरा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने इसका आरोप पिछली गैर-कांग्रेसी सरकारों पर आरोपित करने का प्रयास किया है। महोदय, कई वर्षों से चली आ रही गलत आर्थिक नीतियों के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका आरोप उन्होंने गिगत की केवल दो गैर-कांग्रेसी सरकारों पर मढ़ा है, जो कि सत्ता में केवल डेढ़ वर्ष रही हैं।...

मैं सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि 1985 से 1989-90 तक भी हमारे व्यापार संतुलन में थोड़े की स्थिति बनी रही। जब यह स्थिति है, तो उन्होंने कैसे यह निष्कर्ष निकाल लिया कि यह स्थिति केवल गैर-कांग्रेसी सरकारों के कारण उत्पन्न हुई है? मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूँ कि जब वह वाणिज्यिक बैंकों और विदेश के विभिन्न बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेने का प्रयास करते हैं, तो वह हमें बताएं क्या साल 1985-86 से ही वाणिज्यिक बैंक ऋण और अल्पकालिक ऋण की शुरुआत की गई थी? वही बताएं कि कौन सी परिस्थितियां थीं कि ऐसे ऋण लेने के लिए मजबूर होना

पड़ा था?

...अभी लिए गए ऋणों का लगभग 89 प्रतिशत किरतों तथा ब्याज की अदायगी करने में खर्च हो रहा है।...केवल 11 प्रतिशत राशि ही हमारे विकास कार्य के लिए बचती है। स्थिति तो यह है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगले दो-तीन वर्षों में हमारी स्थिति बहुत खराब तथा खतरनाक स्तर तक पहुंच जाएगी तथा जनता से हम जितना भी ऋण लेने का जवाब कर रहे हैं, यह श्राप पूंजी ब्याज की अदायगी करने में ही खर्च हो जाएगी। हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं।...मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम को क्रियान्वित करते समय राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सरकार, दोनों में बेकार की प्रतिस्पद्धा होती है, चाहे वे किसी भी दल से संबंधित हों तथा इस कारण हमारा देश कर्ज के जाल में फंस गया है। इस प्रकार की प्रतिस्पद्धा करने के स्थान पर यदि हमने उत्पादन वाले कार्यों में धन लगाया होता, तो स्थिति बिल्कुल भिन्न होती। अतः इस स्थिति में पहुंचने के लिए सभी का योगदान है।

...अब मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना

चाहता हूँ, जो उन्होंने 51 प्रतिशत विदेशी पूंजी लाने के लिए आमंत्रित किया है, चाहे वह अनिवासी भारतीय हों या बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल इस सरकार को सतर्क कर देना चाहता हूँ कि वह और अधिक सावधानी बरते तथा उदार औद्योगिक तथा व्यापारिक नीतियों में लघु उद्योगपतियों को बिल्कुल समाप्त न कर दें।...

क्या हम विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपये से 6,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता नहीं दे रहे? तथाकथित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में किसे लाभ मिल रहा है?...सभा के कुछ वर्ग इस आधार पर कि कुछ किसान संपन्न हैं, किसानों को दी जाने वाली 2,000 करोड़ रुपये की राज सहायता का विरोध क्यों कर रहे हैं? ...वर्ष 1991-92 के लिए हमारे विकास व्यय में करीब 4,916 करोड़ रुपये की प्रस्तावित वृद्धि हुई है, जबकि सिंचाई के लिए मुश्किल से 81 करोड़ रुपये दिए गए हैं। समाज सेवा के लिए 1,337 करोड़ रुपये दिए गए हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह विकास विरोधी बजट है।

कतई खतरे में नहीं पड़ेगी हमारी आजादी

मुरली देवड़ा
डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं स्वागत करता हूँ। भारत सरकार द्वारा आर्थिक संकट को हमारी जनता की बेहतरी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर में बदलने का पहली बार गंभीर प्रयास किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बजट पर चर्चा और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस माननीय सभा के इंद्रजीत गुप्त ने कहा कि ये ऋण

और अभिभाषण के बारे में बोला, बल्कि हमारे देश पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के होने वाले प्रभावों पर भी बोला है। मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूँ कि मेरे वामपंथी मित्रों और कभी-कभी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों में यह हीन भावना क्यों आ जाती है कि विश्व बैंक अथवा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण हमारे देश को पूर्णतया अस्थिर कर देंगे? कल इंद्रजीत गुप्त ने कहा कि ये ऋण

हमारी आर्थिक संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता को खतरे में डाल देंगे। परसों भारतीय जनता पार्टी के एक मित्र ने कहा कि सरकार ने हमारी संप्रभुता और यहां तक कि हमारी आत्मा विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को बेच दी है। मैं इस भ्रम को मिटाना चाहता हूँ। इस समय हमारे पास 77 अरब डॉलर का विदेशी ऋण है, जिसमें से लगभग 42 अरब डॉलर हमने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व

बैंक से लिए हैं। पिछले 40 वर्षों से विश्व बैंक से ऋण लेने वालों में हम सबसे आगे रहे, केवल एक वर्ष को छोड़कर, जब चीन ने हमसे ज्यादा ऋण लिया, जब वह विश्व बैंक का सदस्य बना था।... अतः पिछले 40 सालों से भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से आसान और कड़ी शर्तों पर सबसे अधिक ऋण लिया है। उन्होंने हमें अस्थिर कैसे किया? उन्होंने हमारे लिए कौन सी समस्याएं पैदा

जिस पार्टी के लिए अध्यक्ष का चुनाव ही चुनौती हो, वह भाजपा का मुकाबला कैसे करेगी?

संजय कुमार
कांग्रेस में निर्मित संकट की स्थिति बाहर से जैसी दिखाई देती है, अंदरूनी तौर पर वास्तव में वह उससे भी गहरी है। इसके तीन कारण हैं। पहला यह कि पार्टी का जनाधार तेजी से घट रहा है और मतदाता उसमें भरोसा गंवा चुके हैं। चुनाव परिणामों में यही अविश्वास झलकता है। दूसरा यह कि पार्टी से युवा और वरिष्ठ दोनों तरह के नेताओं का पलायन निरंतर जारी है। और तीसरा यह कि वोटर तो छोड़िए, खुद पार्टी के मौजूदा नेतागण ही अपने शीर्ष नेतृत्व में भरोसा अब खो चुके हैं।

हाल ही में जी-23 के कुछ सदस्यों का पार्टी अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों से जैसा टकराव हुआ, वह इस बात का और एक संकेत है कि मामला किताना गम्भीर हो चुका है। जी-23 नेताओं के द्वारा निर्वाचक-नामावली को सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। इस समूह को सुधारवादी कहा जाता है, जो पार्टी के पुराने वफादारों के साथ संघर्ष की मुद्रा में आ चुका है।

इससे पार्टी में मोटियों का विश्वास और घटेगा। उसकी भारत जोड़ो यात्रा को भी विभिन्न सिविल सोसायटी समूहों का समर्थन भले मिल रहा हो, लेकिन उससे कांग्रेस पार्टी का पुनरुत्थान नहीं हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से अब तक 17 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से एक में भी कांग्रेस को जीत नहीं मिली है।

अलबत्ता वह तमिलनाडु, महाराष्ट्र और झारखंड में जरूर सरकार का हिस्सा रही, लेकिन सत्तारूढ़-गठबंधन में उसकी सहभागिता बहुत कम थी। लेकिन बात केवल यहीं तक ही सीमित नहीं थी कि कांग्रेस चुनाव हार रही है, समस्या यह है कि वह बुरी तरह से हार रही है। कुछ राज्यों में तो वह तीसरे या चौथे स्थान पर रही। 17 में से 12 राज्यों में उसका वोट-शेयर भी घट गया।

बड़े नेताओं के पलायन से भी पार्टी को गहरा झटका लगा है। बात केवल दो या तीन नेताओं की नहीं है, यह सूची बहुत लम्बी है। इनमें से कुछ तो ऐसे थे, जो दशकों से पार्टी से जुड़े थे। गुलाम नबी आजाद, कैब्रिट अमरिंदर सिंह, कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। वहीं राहुल गांधी के भरोसेमंद माने जाने वाले युवा-तुर्क ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह सहित कई ऐसे नेताओं ने भी कांग्रेस को विदा कह दिया, जो अतीत में मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री रह चुके थे।

ये ऐसे नेता थे, जो किसी मामूली कारण से पार्टी नहीं छोड़ सकते थे। उनका रोष कहीं गहरा था, जिसकी गांधी परिवार के द्वारा लम्बे समय से अनदेखी की जाती रही थी। वास्तव में आज लोकसभा में कांग्रेस के जितने सांसद हैं, उससे ज्यादा नेतागण बीते बरसों में कांग्रेस छोड़ चुके हैं। मानो इतना काफी नहीं था, तो अब पार्टी के मौजूदा नेताओं में टू-टू-में-में शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होने जा रहे चुनाव की निर्वाचक नामावली को लेकर जी-23 के सदस्य नेतागण अड़ गए हैं।

एक तरफ तो कांग्रेस बड़े जोर-शोर से अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लॉन्च करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ वह अपनी ही पार्टी को जोड़े रखने के लिए संघर्ष कर रही है। जिस तरह से कुछ कांग्रेस नेताओं ने गुलाम नबी आजाद पर हमला बोला है, उससे तो यही लगता है कि गांधी परिवार की खुशामद करने वाले आज भी पार्टी में अति-सक्रिय हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखाई दे रहा है कि 2019 के बाद से पार्टी की क्या बुरी गत हो गई है।

आने वाले दिन तो पार्टी के लिए और चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि उसे न केवल अपना नया अध्यक्ष चुनना है, बल्कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भाजपा से आमने-सामने की टकराव भी लेनी है। यह तो तय है कि राहुल गांधी के फिर से अध्यक्ष बनने से पार्टी को फायदा नहीं होगा। न केवल भारतीय मतदाता उन्हें स्वीकार नहीं कर पाए हैं, बल्कि कांग्रेसियों के बीच भी उनकी स्वीकार्यता नहीं बन सकी है। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले सभी नेतागण पार्टी की बदहाली के लिए राहुल को ही दोषी करार देते हैं। वे राहुल की नेतृत्व-शैली से संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन अगर कांग्रेस ने गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुन लिया, तब भी हालात सुधरने नहीं वाले हैं। जिस पार्टी के लिए एक सर्वमान्य अध्यक्ष का निर्वाचन ही एक चुनौती बन गया हो, वह 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का मुकाबला कैसे कर सकेगी?

कों? ...आखिर हम किसका अनुसरण करें? हमें अन्य राष्ट्रों की गलतियों से भी सीखना चाहिए।

...हमारे वामपंथी मित्र दूसरों की गलतियों से सीखना नहीं चाहते हैं। वे वही गलतियां बार-बार करना चाहते हैं। ... अब विश्व में साम्यवाद नहीं रह गया है। रूसियों और चीनियों ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन हमारे वामपंथी मित्र अभी भी इसे भारत में चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं उन्हें इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में इसे पूर्णतया छोड़ दिया है। मैं आपको बताता हूँ कि बंबई के बड़े उद्योगपति और बहुराष्ट्रीय ग्रुप कलकत्ता में ज्योति बसु से मिलकर तसल्ली महसूस करते हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आर्थिक नीतियों को पूर्णतः उदार कर दिया गया है। लेकिन इसमें क्या गलत बात है, यदि ऐसा पूरे भारत में हो? आप उन नीतियों को केवल पश्चिम बंगाल में ही क्यों लागू करना चाहते हैं? आप नहीं समझते हैं कि भारत आपका देश है? आप इन स्वतंत्रताओं को केवल पश्चिम बंगाल तक ही सीमित क्यों करना चाहते हैं?

...अनेक बातें कही गई हैं। यह तक कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से ऋण लेना अपने आपको बेचना है।... मैं डॉ मनमोहन सिंह को बधाई देता हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को पीछे छोड़ दिया है। इकोनॉमिक सर्वे

में यह कहा गया है कि 1990 और 1991 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से दो ऋण लिए गए। वी पी सिंह की सरकार ने सितंबर, 1990 में 1,173 करोड़ रुपये का ऋण लिया। जनवरी, 1991 में चंद्रशेखर सरकार ने 3,334 करोड़ रुपये का दूसरा ऋण लिया। हमारे वामपंथी मित्र राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का समर्थन कर रहे थे।...हमने भी उनका समर्थन किया और यह एक गलती थी। हमें इस पर पछतावा है।

... आज थाईलैंड, इंडोनेशिया, बेंकाक और दक्षिण कोरिया जैसे देशों का वार्षिक निवेश हमारे 20 वर्षों के कुल निवेश से अधिक है। दुनिया के सभी देश अधिक से अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमने इसे बंद कर दिया है। इसे 40 से 51 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ। मेरे विचार से यह 51 प्रतिशत से भी अधिक होना चाहिए। वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं? आपने कोई ऐसी कंपनी देखी है, जिसकी 90 प्रतिशत अंशधारिता है? मैं सीमेन्स और कॉलगेट कंपनी को जानता हूँ। मुंबई में कई उद्योग हैं, उन्होंने 95 से 100 प्रतिशत अंशधारिता दी है। उन्होंने हमारे लिए क्या कर दिया?...इसलिए इस सरकार को अधिक विदेशी निवेश को अनुमति देनी चाहिए। केवल 51 प्रतिशत नहीं, बल्कि 51 प्रतिशत से भी अधिक।



टिकाऊ खेती में खरपतवार नियंत्रण का महत्व

देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाद्यान्नों की मांग को पूरा करना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। गेहूँ एवं धान खाद्यान्न की ऐसी फसलें हैं, जिनमें गरीबी और मुख्यमरी की समस्या से लड़ने की अद्भुत क्षमता है। धान, गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा हमारे देश की खरीफ की प्रमुख खाद्यान्न फसल हैं। अधिक पैदावार देने वाली खाद एवं सिंचाई का अधिक उपयोग करने में एवं उच्चतम किस्मों के प्रचलन से लगभग पिछले 2 दशकों में अनाज वाली फसलों एवं दलहन एवं तिलहन की पैदावार में व्यापक वृद्धि हुई है। फिर भी इसकी औसत पैदावार इसकी क्षमता से काफी कम है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिये सुधरी खेती को सभी प्रायोगिक विधियों को अपनाया आवश्यक है और जब तक हम उन वैज्ञानिक तरीकों को नहीं अपनाते हैं, उपज में आपेक्षित वृद्धि संभव नहीं है।

देश की तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण-पोषण के लिये प्रति इकाई क्षेत्र समय एवं साधन से अधिक से अधिक उत्पादन करना नितांत आवश्यक है। इसके लिये सघन कृषि प्रणाली अपनाएने के साथ-साथ उत्तम किस्म का चुनाव, सही समय पर बुवाई, संतुलित मात्रा में पोषक तत्व देना, उचित समय पर सिंचाई करना, फसल को कीड़ों, बीमारियों एवं खरपतवारों से बचा कर रखना बहुत जरूरी है जिससे न केवल फसल की पैदावार बढ़ेगी, वरन् उत्पादन कारकों की क्षमता भी बढ़ेगी तथा किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

खरपतवारों से हानियाँ

खरपतवार जो उपलब्ध पोषक तत्वों, नमी, प्रकाश एवं स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा फलस्वरूप फसल की पैदावार एवं गुणवत्ता में भारी कमी ला देते हैं।
- खरपतवार फसल में लगने वाले रोगों के जीवाणुओं एवं कीट-व्याधियों को भी आश्रय देते हैं।
- एक अनुमान के अनुसार खरपतवार विभिन्न फसलों की पैदावार में 33 प्रतिशत तक की कमी करने की क्षमता का ध्यान न रखकर कहा जा सकता है कि वर्तमान की संभावित उत्पादन स्तर में ही खाद्यान्न की 103 मिलियन टन, दलहन की 15 मिलियन टन एवं तिलहन की 10 मिलियन टन की कमी हो रही है।

प्रमुख खरपतवार

इन फसलों में प्रभावी खरपतवार नियंत्रण के लिये उसमें उगने वाले खरपतवारों की जानकारी होना अति आवश्यक है। खरीफ एवं रबी फसलों में उगने वाले खरपतवारों को मुख्यतः तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। खरपतवारों की रोकथाम कैसे करें फसलों में खरपतवारों की रोकथाम

निम्न तरीकों से की जा सकती है।

- स्टेल् सीड बेड (बुवाई के पहले खरपतवारों को नष्ट करना) फसलों की बुवाई से पहले खाली खेत की हल्की सिंचाई करने से अधिकांश खरपतवार ऊग आते हैं। जब ये 2-3 पत्तों के हो जाएं तो उन्हें शाकनाशी (ग्लायफोसेट अथवा पैराक्वाट) का 0.50 प्रतिशत घोल) द्वारा अथवा यांत्रिक विधि से जुताई करके नष्ट किया जा सकता है जिसे मुख्य फसल में खरपतवारों की संख्या में काफी कमी आ जाती है।
शुद्ध एवं साफ बीज का प्रयोग - बुवाई के समय खरपतवार रहित एवं प्रमाणित बीज का प्रयोग करके खरपतवारों की संख्या पर काबू पाया जा सकता है। कुछ फसल के बीजों को बुवाई के पहले छन्ने से साफ करने पर खरपतवारों के बीज आकार में छोटे होने के कारण नीचे गिर जाते हैं। जैसे गेहूँ में गेहूँ के मामा का बीज।

किस्मों का चुनाव

एवं बुवाई विधि

जहां पर खरपतवार की रोकथाम के साधनों में कमी हो वहां पर फसल की ऐसी प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए जिनकी प्रारंभिक बढ़वार खरपतवार की तुलना में अधिक हो। ऐसी प्रजातियों खरपतवारों से प्रतिस्पर्धा करके उन्हें नीचे दबा देती हैं। छिटकवा विधि के बजाय कतारों में बुवाई करने से खरपतवारों की संख्या में कमी पायी जाती है। तथा साथ ही साथ उनके नियंत्रण में भी आसानी रहती है।
जिरोटिलेज एवं फर्ब्स - धान-गेहूँ फसल चक्र में धान की कटाई के तुरन्त बाद (बिना खेत की जुताई के) जीरो टिल मशीन से गेहूँ की बुवाई करने पर 'फेलरिस माइनर' खरपतवार की संख्या में काफी कमी पाई गई है। इसके अतिरिक्त फर्ब्स मशीन द्वारा बनाई गई मेडों पर गेहूँ की बुवाई करने से भी

फेलरिस माइनर की संख्या में काफी कमी आती है। ये विधियाँ हमारे देश के पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय हैं।

उचित फसल चक्र अपनाकर - एक ही फसल को लगातार एक ही खेत में बोने से खरपतवारों की संख्या काफी अधिक हो जाती है। तथा उसके नियंत्रण में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। अतः आवश्यक है कि एक फसल को बार-बार एक ही खेत में न बोया जाय तथा उचित फसल-चक्र अपनाया जाये।

धान-गेहूँ फसल चक्र में फेलरिस माइनर की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी पाई गई है। अतः इस फसल चक्र में गन्ना, बरसीम या आलू की खेती से इस खरपतवार में काफी कमी पाई गई है। अन्तरवर्ती फसलें उगाकर - कुछ फसलें जैसे मक्का जिनके कतारों के बीच की दूरी 60-90 सेंमी. तक होती है, खरपतवार आसानी से इन कतारों के बीच उगाकर फसल की पैदावार को कम कर देते हैं। इन कतारों के बीच यदि किसान भाई जल्दी बढ़ने वाली तथा कम समय की फसलें जैसे लोबिया, मूंग आदि को उगायें तो खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है तथा साथ ही साथ अतिरिक्त पैदावार भी मिल सकती है।

यांत्रिक विधि - खरपतवारों पर काबू पाने की यह सरल एवं प्रभावी विधि है। दलहनी एवं तिलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिये खरपतवारनाशक दवाइयों के बजाय निकाई-गुड़ाई की सिफारिश की जाती है। इन फसलों में 30-35 दिन बाद एक बार निराई-गुड़ाई करके खरपतवारों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाया जा सकता है। कतारों में बोई गई फसलों में हो चलाकर भी खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। परन्तु यांत्रिक विधि से खरपतवार नियंत्रण में समय और मजदूर अधिक लगते हैं जिससे प्रति इकाई क्षेत्रफल में लागत अधिक आती है।

खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग - समय को देखते हुए खरपतवारों का नियंत्रण शाकनाशी रसायनों द्वारा करने से जहां एक ओर खरपतवारों का उचित समय पर नियंत्रण हो जाता है वहीं दूसरी ओर लागत एवं समय की भी बचत होती है। लेकिन खरपतवारनाशकों का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना होगा कि उसकी उचित सान्द्रता को उचित विधि द्वारा उपयुक्त समय पर प्रयोग करें ताकि इनसे समुचित लाभ प्राप्त हो सके।

ज्वार के प्रमुख रोग एवं प्रबंधन

अर्गट या गूदिया रोग

रोग के लक्षण - दानों के बाहरी भाग पर गाढ़ा, रंगहीन अथवा हल्का गुलाबी चिपचिपा साव बूदों के रूप में जमा होता है। बाजरा व इस्केमस घास इस रोगकारक के अन्य परपोषी हैं।
रोकथाम - खेत के आसपास अन्य परपोषी पौधों को हटा दें। रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी घोलकर (0.2 प्रतिशत) छिड़काव करें।

कंडवा रोग

रोग के लक्षण - ज्वार की फसल में चार विभिन्न प्रकार के कंडवा रोग लगते हैं। इनका पता भुट्टा आने पर ही चलता है। आवृत कंडवा में भुट्टा के सारे बीज प्रभावित होते हैं जो काले रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं। अनावृत कंडवा में भी सारे बीज प्रभावित होकर गांठे बनती हैं- जिस पर हल्की सफेद रंग की परत होती है। दीर्घ कंडवा में भुट्टा के कुछ दाने संक्रमित होकर लम्बी बेलनाकार सरचनाएं बनती हैं। शीर्ष कंडवा में पूरा भुट्टा ही एक गांठ के रूप में

बदल जाता है।

शीर्ष कंडवा

रोकथाम - खेत में रोगग्रस्त सिद्ध दिखाई देते ही कागज या कपड़े की थैली से इन्हें ढककर काट लें व जलाकर नष्ट कर दें। बीजों की बुवाई पूर्व थाइरम 4 ग्राम या कार्बोक्सिन 2 ग्राम/किलो बीज दर से उपचारित करें।

पत्ती धब्बा रोग

रोग के लक्षण - ज्वार पर ग्यारह प्रकार के विभिन्न पत्ती धब्बा रोगों का आक्रमण होता है। ये रोग देशी किस्मों पर व्यापकता से फैलते हैं। ये पूर्ण अंगमारी, लाल धब्बा, जोनेट धब्बा, टारगेट धब्बा, कज्जलीधारी, भूरा धब्बा, खुरदरा धब्बा, डेऊवसेलेरा पत्ती झुलसा प्रमुखता से है।
रोकथाम - ये रोग बीजोद्भूत होते हैं साथ ही फसल अवशेषों में जीवित रहते हैं अतः रोगग्रस्त अवशेषों को इकट्ठा कर जला दें। रोगग्रस्त फसल के बीज बुआई के काम में न लें। रोगरोधी किस्में जैसे सीएसवी 10, 15, 17, सीएचएच 5, 6, 9, 14 की बुवाई करें। चारे के लिए देशी किस्में

बोयें। कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/ किलो बीज की दर से उपचारित करें। रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर मैकोजेब 0.2 प्रतिशत का छिड़काव करें।

चारकोल तना सड़न रोग

रोग के लक्षण - इस रोग से तने के निचले भाग अथवा जड़ों पर पहले हल्के रंग के बाद में काले रंग के धब्बे बनते हैं तथा उसमें सड़न प्रारंभ हो जाती है। बहुधा इस प्रकार के पौधे झुण्डों में होते हैं तथा सूखकर गिर जाते हैं, इससे उपज में बहुत अधिक हानि होती है।

रोकथाम - यह रबी की ज्वार में नमी कम होने पर अधिक होता है, अतः नमी का मूदा में संरक्षण करें। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या अधिक या बहुत कम नहीं होनी चाहिए। ऐसी किस्में जो दाना पकते समय हरी रहती हों बोनी चाहिए क्योंकि इनमें चारकोल तना सड़न नहीं आता है।



सरसों में व्याधि प्रबंध

रोग एवं कीट व्याधियों का प्रबंधन वैसे तो सरसों की फसल पर एक दर्जन से अधिक रोग व कीट हानि पहुंचाते हैं परन्तु प्रमुख रोग एवं कीट के नियंत्रण से भरपूर पैदावार की जा सकती है।

पत्ती झुलसन रोग - यह सरसों के झुलसा रोग के नाम से भी जाना जाता है इस रोग के लक्षण पत्ती पर गहरे भूरे गोल-गोल धब्बों के रूप में आते हैं तथा उपज में कमी के साथ तेल की मात्रा भी कम करते हैं। बचाव हेतु मेन्कोजेब 45 नामक दवा 2.5 ग्राम /लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें 2-3 छिड़काव 15 दिन के अंतराल से करें।

श्वेत किट्ट या सफेद फफोला (व्हाइट स्ट) रोग- शीत ऋतु में जब तापमान कम एवं कोहरा होने पर यह रोग बहुत तेजी से फैलता है इसके लक्षण पत्ती की निचली सतह पर सफेद दही जैसे संरचनाओं जैसे आकार के होते हैं बाद में पुष्प वृन्त एवं फलियों पर भी लक्षण दिखाई देते हैं फली अनियमित आकार की टेड़ी-मेड़ी कंकड़ा जैसी आकृति की हो जाती है नियंत्रण हेतु रिडोमिल एम जेड 72 नामक दवा 2 ग्राम/लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें या 2.5 ग्राम मेन्कोजेब/लीटर पानी का छिड़काव 10-15 दिन के अंतराल पर दो बार करें।

चूर्णिल आसिता (पाउड्री मिल्ड्यू) - यह

रोग तापमान बढ़ने पर अधिक तेजी से फैलता है रोग पत्तियों, तने व फलियों पर सफेद चूर्ण (पाउडर) जैसे संरचनाओं के रूप में फैलता है। नियंत्रण हेतु चुलनशील गंधक या सल्फेक्स 2 किलोग्राम दवा 800 लीटर पानी में घोल बनाकर/हे. के हिसाब से छिड़काव करें।

तना सड़न या पोलियो रोग - एक ही खेत में बार-बार सरसों की फसल बोने से यह रोग बढ़ता है। इसके धब्बे सबसे पहले तने के निचले हिस्से में गोल-गोल आकृति के रूप में आते हैं, बाद में ऊपर तक फैल जाते हैं पौधा कमजोर होकर एवं तना पोला होकर रोगग्रस्त स्थान से टूट जाता है।

नियंत्रण हेतु - फसल चक्र अपनाएं एवं रोगग्रस्त पौधों को एकत्रित कर नष्ट करें पहले तने के निचले हिस्से में गोल-गोल आकृति के रूप में आते हैं, बाद में ऊपर तक फैल जाते हैं पौधा कमजोर होकर एवं तना पोला होकर रोगग्रस्त स्थान से टूट जाता है।

नीट नियंत्रण दगीला बग/बगराड़ा कीट (पेन्टेड वग)-

राई सरसों की फसल को यह कीट दो बार नुकसान पहुंचाता है जब पौधे छोटे होते हैं तब और जब फली बनती है तब, कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों ही इसे चूसते हैं जिसकी पत्तियों और पौधों पर सफेद धब्बे स्पष्ट दिखाई देते हैं नियंत्रण हेतु पौधों के अवशेषों को नष्ट कर दें। मेडों को साफ रखें, फसल काटने के तुरन्त बाद गहरी जुताई करें जिससे प्रकोप कम होगा। डायमिथियेट या मेटासिस्टावस 25 ई.सी. 500 मि.मी. दवा 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

माहू या चैपा (एफिड) - इस कीट को लसा के नाम से भी जाना जाता है यह छोटे पंख एवं पंख रहित दोनों तरह के हरे, पीले रंग के होते हैं। कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों ही बढ़ने वाले भागों फूलों कलियों, फलियों आदि का झुण्डों में चिपककर रस चूसते हैं, पौधों की बढ़वार रुक जाती है। पैदावार एवं तेल की मात्रा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है नियंत्रण हेतु समय पर बोनी करें, प्रकोप की 80 दिन की फसल पर छिड़काव करें, 2 प्रतिशत लहसुन का अर्क बीजोपचार एवं छिड़काव दोनों के लिए उपयुक्त एवं रोग को कम करता है।



अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति पर जानलेवा हमले की कोशिश, बाल-बाल बची

अर्जेंटीना। स्थानीय समयानुसार यह घटना रात करीब साढ़े नौ बजे हुई। कहा जा रहा है कि जैसे ही हमलवार ने उपराष्ट्रपति पर पिस्टल तानी, वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे पीछे धकेल दिया, जिससे वह बाल-बाल बच गई। अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज पर जानलेवा हमले की खबर सामने आई है। हालांकि, इस हमले में वह बाल-बाल बच गई। जानकारी के मुताबिक, क्रिस्टीना के घर के बाहर ही एक व्यक्ति ने उन पर पिस्टल तान दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय समयानुसार यह घटना रात करीब साढ़े नौ बजे हुई। कहा जा रहा है कि जैसे ही हमलवार ने उपराष्ट्रपति पर पिस्टल तानी, वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे पीछे धकेल दिया, जिससे वह बाल-बाल बच गई। सुरक्षाकर्मियों ने हमलवार को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक, हमलवार ब्राजील मूल का बताया जा रहा है। देश के वित्त मंत्री सर्जियो मस्सा ने इस घटना को हत्या की कोशिश बताया है।



चीन में कोरोना के चलते चेंगदू व शेनझेन में लगा लॉकडाउन, इसाइल ने फिट किया सीरिया पर हमला

बीजिंग। चीन के चेंगदू और शेनझेन में कोरोना का प्रसार एक बार फिर बढ़ रहा है। चेंगदू में 19 और शेनझेन में 62 नए मामले सामने आए। इसे देखते हुए क्षेत्र में कोविड प्रतिबंधों के तहत सख्ती कर दी गई है। यहां सबसे घनी आबादी के बाओआन जिले में अगले तीन दिनों तक किसी भी सार्वजनिक जगह या घर पर जमावड़े की मनाही कर दी गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नए सेमेस्टर के लिए स्कूल खुलने की तारीख भी टाल दी है। पहले सारे स्कूल बहुरूपितावर से खुलने थे। शेनझेन के हुआकियांगबेई स्थित दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में 4 दिनी लॉकडाउन भी लगा है। इसाइल ने सीरिया के दो हवाई अड्डों को बनाया निशाना इसाइल ने बुधवार रात सीरिया के दो हवाई अड्डों के निशाना बनाकर हवाई हमले किए। पहला हमला अलेपो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ, जहां हथियार लेकर पहुंचे ईरान के विमान को निशाना बनाया गया। दूसरा हमला दमिश्क एयरपोर्ट के पास हुआ। दोनों ही जगहों पर इसाइल के तरफ से मिसाइलें दागी गईं। सीरिया की न्यूज एजेंसी सना ने कहा, इसाइल ने 4 मिसाइलें दागी हैं। हमले के बाद एयरपोर्ट पर भारी नुकसान हुआ है लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसाइली सैन्य प्रवक्ता ने इस पर बयान देने से इनकार कर दिया। मिस्र की स्वेज नहर के भीतर छिछले पानी में तेल का एक टैंकर फंस गया। इससे करीब सवा सात घंटे तक के लिए वैश्विक जलमार्ग बाधित रहा। हालांकि बाद में पोट को वहां से निकाल लिया गया। फंसे हुए 'एफिनटी वी' पोट पर सिंगापुर का झंडा लगा था। बताया गया कि तकनीकी खराबी के कारण पोट नहर के किनारे से टकरा गया था।

टाइटेनिक डूबने के 110 साल बाद सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीरें



वाशिंगटन। कई साल से समुद्र में डूबे टाइटेनिक जहाज पर अन्वेषण कर रहे ओशनगोट टीम के सदस्यों ने आखिरकार मुकाम हासिल करके दुनिया को चौंका दिया है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक टीम ने समुद्र में सौ साल से ज्यादा समय से डूबे टाइटेनिक जहाज के विभाजित हिस्सों की साफ, विहंगम तस्वीर दुनिया के सामने साझा की और इसके वीडियो में जहाज के विशाल 15 टन के लंगर को भी दिखाया गया। ओशनगोट टीम द्वारा ली गई टाइटेनिक जहाज की तस्वीर, वीडियो को इस सप्ताह सोशल प्लेटफॉर्म पर साझा किया है, जिसमें 12,500 फीट तक की गहराई में जमा जहाज के अद्भुत चित्र हैं। टाइटेनिक जहाज साल 1912 में डूबा था जिसका आधा हिस्सा समुद्र के तल में बैठ गया। रिपोर्ट के अनुसार, साझा किए गए, एक मिनेट के लंबे वीडियो में दर्शक 110 साल पुराने जहाज के अलग-अलग भाग, पोटसाइंड एंकर और एंकर चेन के साथ-साथ मलबे के अन्य हिस्सों को भी देख सकते हैं।

चीन में मुस्लिमों पर जुल्म, डिटेनशन सेंटरों में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जबरन नसबंदी...चौंकाने वाली रिपोर्ट

बीजिंग। चीन ने संयुक्त राष्ट्र (संरा) मानवाधिकार कार्यालय की एक रिपोर्ट जारी होने पर हैरान जताई है, जिसमें उसपर शिनजियांग प्रांत में उद्गर मुसलमानों के 'मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन' का आरोप लगाया गया है। चीन ने रिपोर्ट को अवैध और अमान्य करार देते हुए कहा कि अमेरिका ने उसे रोकने के लिए यह रिपोर्ट गढ़ी है। निवर्तमान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट, जिनेवा में नाटकीय अंदाज में जारी की गई। बैचलेट चीन के साथ लंबे समय तक चले राजनयिक विवाद के बाद मई में शिनजियांग में गई थीं, जिसके बाद यह रिपोर्ट जारी की गई है।

चीन ने रिपोर्ट जारी करने पर आश्चर्य जताते हुए इसपर कड़ा

विरोध दर्ज कराया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने यहां एक मीडिया



बीजिंग में रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा, 'तथाकथित आकलन अमेरिका और कुछ पश्चिमी ताकतों द्वारा रचा और तैयार किया गया है। यह पूरी तरह से अवैध और अमान्य है।' चिली की पूर्व राष्ट्रपति बैचलेट ने

अत्यधिक दबाव के बीच आखिरकार बीजिंग के विरोध को दरकिनार कर दिया और बुधवार

को अपने कार्यकाल के अंतिम दिन रिपोर्ट जारी की। मुस्लिमों पर अत्याचार रिपोर्ट में कहा गया है कि शिनजियांग में उद्गर और अन्य मुस्लिम जातीय समूह के लोगों को सरकार द्वारा जबरन नजरबंद

रखना मानवता के खिलाफ अपराध के दायरे में आ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपनी आतंकवाद और उग्रवाद रोधी नीतियों के तहत मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र, विश्व बिरादरी और खुद चीन से इस पर 'तत्काल ध्यान' देने का आह्वान किया है। पश्चिमी राजनविकों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट लगभग तैयार थी, लेकिन बैचलेट का चार साल का कार्यकाल पूरा होने से कुछ ही मिनटों पहले इसे जारी किया गया। कई पत्रकारों, स्वतंत्र मानवाधिकार समूहों ने शिनजियांग में वर्षों से मानवाधिकार उल्लंघन पर काफी कुछ लिखा है। बैचलेट की इस रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र तथा उसके सदस्य देशों की मुहर लगी है। इसके जारी होने के बाद विश्व

संस्था में चीन के प्रभाव पर बहस छिड़ गई। रिपोर्ट जारी होने से कुछ देर पहले संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत झांग जून ने कहा था कि बीजिंग इस रिपोर्ट का 'दुद्रुता से विरोध' करता है। मानवाधिकार समूहों और जापान की सरकार ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया है। जापान रिपोर्ट पर टिप्पणी करने वाले शुरुआती देशों में से एक था। रिपोर्ट गुरुवार सुबह एशिया में जारी की गई थी। जापान के शीपू सरकारी प्रवक्ता ने चीन से शिनजियांग क्षेत्र में पारदर्शिता और मानवाधिकार की स्थिति में सुधार करने का आग्रह किया। मानवाधिकार संगठनों 'ह्यूमन राइट्स वॉच' और 'एम्नेस्टी इंटरनेशनल' ने संयुक्त राष्ट्र और सरकारों से मानवाधिकारों के हनन की एक स्वतंत्र जांच करने का आह्वान किया।

बीजिंग: श्रीलंका के अग्रदत्त राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका लौटने वाले हैं। देश में ऐतिहासिक आर्थिक संकट और इसके कारण पैदा हुए राजनीतिक संकट व अशांति के बाद उन्होंने देश छोड़ दिया था। उनकी जगह रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति के तौर पर देश की बागडोर संभाल रहे हैं। श्रीलंका के रक्षा अधिकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे के जल्द स्वदेश लौटने की जानकारी दी है। उनकी जगह रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति के तौर पर देश की बागडोर संभाल रहे हैं।

स्वदेश लौट सकते हैं। डेली मिरर ने राजपक्षे के करीबी रूस में श्रीलंका के पूर्व राजदूत उदयंगा वीरातुंगा के हवाले से यह खबर दी है। उन्होंने संकेत दिया कि



राजपक्षे वापस थाईलैंड से देश लौट सकते हैं। इससे पहले उन्होंने संकेत दिया था कि 24 अगस्त को स्वदेश लौट सकते हैं। गोतलब है कि गोतबाया राजपक्षे पिछले महीने मालदीव भाग गए थे और उसके बाद वहां से सिंगापुर भाग गए। उन्होंने मंडिकल वीजा पर सिंगापुर में प्रवेश किया और वहां रहने के लिए इस दो बार

बढ़ाया गया। चूंकि इसके बाद उनके वीजा आगे नहीं बढ़ाया जा सका इसलिए राजपक्षे और उनकी पत्नी थाईलैंड के लिए रवाना हुए। थाई सरकार ने उन्हें आश्रय दिया था कि वे वहां 90 दिनों तक रह सकते हैं। हालांकि, राजपक्षे को थाईलैंड में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। फिलहाल, पूर्व राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे अपनी पत्नी लोमा राजपक्षे के साथ बैंकॉक के एक होटल में ठहर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राजपक्षे के नेतृत्व वाली एसएलपीपी द्वारा उनसे अनुरोध किए जाने के बाद राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने उनकी वापसी की व्यवस्था की है। 19 अगस्त को एसएलपीपी के महासचिव सागर करियावासम ने कहा कि राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के साथ हुई बैठक में ये अनुरोध किया गया था।

जर्मनी में पायलटों की हड़ताल, उड़ानें निरस्त होने पर दिल्ली में हंगामा

बर्लिन : जर्मनी के पायलट एक दिनी हड़ताल पर हैं। इसके कारण देश की अग्रणी लुफ्थान्सा एयरलाइंस ने 800 से ज्यादा फ्लाइट निरस्त कर दी है। इसके कारण 1.30 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए हैं। उड़ान निरस्त होने से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बीती रात यात्रियों ने हंगामा

किया। इसके कारण एयरपोर्ट पर आवाजाही में बाधा पड़ी। जर्मनी की पायलट यूनियन ने विभिन्न मांगों को लेकर आज हड़ताल का एलान किया है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक, पायलटों की हड़ताल के चलते लुफ्थान्सा एयर लाइन की 800 उड़ानें रद्द होने की संभावना है। अधिकारियों का कहना

है कि इतनी बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने के कारण करीब 1.30 लाख यात्रियों पर असर पड़ सकता है। यात्रियों ने की रिफंड या वैकल्पिक उड़ान की मांग-आईजीआई एयरपोर्ट के डीसीपी ने बताया कि रात करीब 12 बजे 150 से ज्यादा लोगों की भीड़ एयरपोर्ट के

डिपार्चर गेट नं. 1 व टर्मिनल नंबर 3 के सामने जमा हो गई। ये लोग लुफ्थान्सा की फ्लैगशिप एयरलाइंस के डीसीपी ने बताया कि रात करीब 12 बजे 150 से ज्यादा लोगों की भीड़ एयरपोर्ट के

डिपार्चर गेट नं. 1 व टर्मिनल नंबर 3 के सामने जमा हो गई। ये लोग लुफ्थान्सा की फ्लैगशिप एयरलाइंस के डीसीपी ने बताया कि रात करीब 12 बजे 150 से ज्यादा लोगों की भीड़ एयरपोर्ट के

डिपार्चर गेट नं. 1 व टर्मिनल नंबर 3 के सामने जमा हो गई। ये लोग लुफ्थान्सा की फ्लैगशिप एयरलाइंस के डीसीपी ने बताया कि रात करीब 12 बजे 150 से ज्यादा लोगों की भीड़ एयरपोर्ट के

डिपार्चर गेट नं. 1 व टर्मिनल नंबर 3 के सामने जमा हो गई। ये लोग लुफ्थान्सा की फ्लैगशिप एयरलाइंस के डीसीपी ने बताया कि रात करीब 12 बजे 150 से ज्यादा लोगों की भीड़ एयरपोर्ट के

डिपार्चर गेट नं. 1 व टर्मिनल नंबर 3 के सामने जमा हो गई। ये लोग लुफ्थान्सा की फ्लैगशिप एयरलाइंस के डीसीपी ने बताया कि रात करीब 12 बजे 150 से ज्यादा लोगों की भीड़ एयरपोर्ट के

पाकिस्तानी जज को धमकाने के मामले में इमरान की अग्रिम जमानत 12 सितंबर तक बढ़ी

इस्लामाबाद। एक जज को धमकाने के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अग्रिम जमानत एक बार फिर बढ़ गई है। इस्लामाबाद स्थित आतंकवादरोधी अदालत ने इमरान खान को अब 12 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत दे दी है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से इमरान खान पर आरोप लगाया गया था कि वे भड़काऊ भाषण देकर देश की जनता को सरकार, अदालत और सेना के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। भड़काऊ भाषण के आरोप में उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही

थी। आरोप था कि बीते 20 अगस्त को इस्लामाबाद की एक सभा में उन्होंने पाकिस्तान की एक न्यायाधीश जेबा चौधरी को धमकी दी थी। इसके अलावा कई अधिकारियों और सरकार के खिलाफ अपत्तिजनक बातें करने के आरोप लगाए गए थे। सरकार ने इमरान के भाषण को भड़काऊ माना है। आरोप लगाया गया था कि इसके जरिए इमरान खान देश की जनता को सरकार, न्यायालय और सेना के खिलाफ भड़का कर देश में गृहयुद्ध कराना चाहते थे। जैसे ही मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया, सरकार और



पुलिस सक्रिय हो गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी

अथॉरिटी ने इमरान के भाषण के लाइव प्रसारण पर रोक लगा दी।

उनके भाषणों को लाइव न प्रसारित करने का आदेश जारी किया गया। पुलिस ने इस मामले में इमरान खान पर आतंकवाद निरोधी कानून की धारा सात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इमरान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके घर बनीगाला भी पहुंची थी लेकिन लोगों की भारी भीड़ देखते हुए उसे लौटना पड़ा। समर्थकों ने इमरान की गिरफ्तारी होने पर देशभर में बवाल होने की चेतावनी दी थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका

दायर की थी, जिस पर बीते 22 अगस्त को तीन दिन के लिए उनकी जमानत मंजूर कर दी गयी थी। जमानत के तीन दिन बीतने पर इमरान 25 अगस्त को स्थित आतंकवादरोधी अदालत में पेश हुए, तब अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर एक सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इमरान खान फिर आतंकवादरोधी अदालत में पेश हुए। न्यायाधीश राजा जवाद अब्बास हसन ने उनकी अंतरिम जमानत 12 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है।

ताइवान के सैनिकों ने पहली बार चीनी ड्रोन को मार गिराया

ताइपे। चीन-ताइवान के बीच तनाव हर दिन एक नई घटना के साथ बढ़ता जा रहा है। ताजा मामले में ताइवानी सैनिकों ने उसके वायु क्षेत्र में प्रवेश कर रहे एक ड्रोन को मार गिराया। किनमें डिफेंस कमांडो ने बताया कि ड्रोन दोपहर को चीनी तट के पास शियू द्वीप के प्रतिबंधित वायु क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। पहले चेतावनी स्वरूप फायरिंग की गई, लेकिन इसके बावजूद ड्रोन अपनी जगह पर उड़ता रहा। इसके बाद उसे मार गिराया गया।

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नेन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद



उपयोग में लाया जाने वाला ड्रोन था। एक दिन पहले ताइवान ने इसके तीन ड्रोंपों के ऊपर दिखे चीनी ड्रोन को लक्ष्य चेतवानी दी गई थी। हालांकि चीन ने उसके आरोप को खारिज कर दिया था।

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नेन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद उपयोग में लाया जाने वाला ड्रोन था। एक दिन पहले ताइवान ने इसके तीन ड्रोंपों के ऊपर दिखे चीनी ड्रोन को लक्ष्य चेतवानी दी गई थी। हालांकि चीन ने उसके आरोप को खारिज कर दिया था।

जॉनसन एंड जॉनसन चुकाएगी 323 करोड़, दवा से हजारों लोगों की मौत पर दिया मुआवजा

वाशिंगटन। जानी-मानी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने अमेरिकी राज्य न्यू हैम्पशायर को करीब 323 करोड़ रुपये मुआवजा देने पर सहमत हो गई। यह मुआवजा कंपनी की अपीम आधारित दवा की लत से राज्य में हजारों लोगों की मौत व पीड़ितों के इलाज के एवज में दिया जाएगा। दद निवारक के तौर साल 2000 से यह दवा ली जा रही थी, इसकी चपेट में अधिकतर बुजुर्ग आए। जॉनसन एंड जॉनसन और सहयोगी कंपनी पर न्यू हैम्पशायर समेत कई राज्यों व पीड़ितों ने केस किए हैं। फरवरी में राष्ट्रीय समझौते से न्यू हैम्पशायर अलग रहा था। गवर्नर क्रिस सुनुनु ने कहा, कंपनी ने जो कुछ किया, भविष्य में वैसा न हो। मुकदमे में कहा गया कि जॉनसन ने भ्रामक दावे किए कि दवा घातक नहीं है। जॉनसन और उसकी सहयोगी जेनसन फार्मा हमेशा अड़े रहे कि उनकी दवा की लत बहुत कम मामलों में लगती है। ताजा समझौते के बाद भी कहा, इसे आरोपों स्वीकारोफि न समझें। लंबित मुकदमों को वह लड़ती रहेगी। न्यू हैम्पशायर को फरवरी में 2.65 करोड़ डॉलर 9 साल में मिलते। ताजा समझौते में उसे एकमुश्त 4.05 करोड़ डॉलर (323 करोड़ रुपये) मिलेंगे।

अमेरिका में दवा कंपनियों, वितरकों, फार्मसी ने ओपिओइड्स व अन्य दवाओं से मीलों व नुकसान के लिए 4,000 करोड़ डॉलर (3.18 लाख करोड़ रुपये) के समझौते किए हैं। 5 लाख को गंवानी पड़ी जान साल 2000 से अब तक इस दवा, अन्य वैध

ओपिओइड्स व अवैध मादक पदार्थों से अमेरिका में 5 लाख लोग मारे गए हैं। न्यू हैम्पशायर में 2016 में 500 मौतें हुईं, जो 2000 के मुकाबले 10 गुना थीं। इस वजह से अमेरिकी दवा प्रवर्तन ने राज्य को सबसे ज्यादा प्रभावित बताया।



भ्रष्टाचार मामले में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की पत्नी को भी जेल

कुआलालंपुर। मलेशिया की एक अदालत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की पत्नी रोस्माह मंसूर को भी 12 साल की सजा सुनाई है। रोस्माह को पति के कार्यकाल में रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराया गया और उनके पति भी जेल जा चुके हैं। अदालत ने उन्हें हर एक मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई और 97 करोड़ रिंगिट का जुर्माना भी लगाया। नजीब को पहले ही मलेशियाई विकास बरहदा कोष (एमडीबी) के सरकारी धन के गबन के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और पिछले सप्ताह उन्हें जेल भेज दिया गया था। रोस्माह मंसूर को बीनियो द्वीप के स्कूलों को सौर ऊर्जा पैनल लगाने करने की परियोजना का काम एक कंपनी को दिलाने के लिए 2016 और 2017 के बीच 65 लाख रिंगिट रिश्वत (15 लाख अमेरिकी डॉलर) मांगने और उसे स्वीकार करने के तीन मामलों

में दोषी ठहराया गया। अदालत ने उन्हें हर एक मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई और उन पर 97 करोड़ रिंगिट का जुर्माना भी लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। शीपू अदालतों में उनकी अपील लंबित होने तक वह जमानत के

लिए गृहण लगा सकती हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद जैनी मजलान ने कहा कि अभियोजकों ने यह साबित कर दिया है कि रोस्माह मंसूर ने रिश्वत मांगी और उसे स्वीकार भी किया था। कर्नेगी फैसले के खिलाफ अपील हालांकि उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है और अब वह फैसले के खिलाफ अपील कर सकती हैं। रोस्माह ने कोर्ट में कहा कि जो कुछ भी हुआ, उससे वह काफी दुखी हैं। रोस्माह की लाइफ स्टायल हमेशा आलोचकों के लिए चर्चा का विषय थी। एक बार वह अपने हैंडबैग की वजह से खबरों में आ गई थीं। नजीब के सत्ता से जाने के बाद उनके पारिवारिक टिकानों पर लगातार छापेमारी की गई। इसमें लग्जोरियस हैंड बैग्स से लेकर 423 घड़ियां, 14 ताज और दूसरी ज्वेलरी मिली। साथ ही साथ 246 मिलियन डॉलर कैश भी उनके घर से बरामद हुआ था।

लिए गृहण लगा सकती हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद जैनी मजलान ने कहा कि अभियोजकों ने यह साबित कर दिया है कि रोस्माह मंसूर ने रिश्वत मांगी और उसे स्वीकार भी किया था। कर्नेगी फैसले के खिलाफ अपील हालांकि उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है और अब वह फैसले के खिलाफ अपील कर सकती हैं। रोस्माह ने कोर्ट में कहा कि जो कुछ भी हुआ, उससे वह काफी दुखी हैं। रोस्माह की लाइफ स्टायल हमेशा आलोचकों के लिए चर्चा का विषय थी। एक बार वह अपने हैंडबैग की वजह से खबरों में आ गई थीं। नजीब के सत्ता से जाने के बाद उनके पारिवारिक टिकानों पर लगातार छापेमारी की गई। इसमें लग्जोरियस हैंड बैग्स से लेकर 423 घड़ियां, 14 ताज और दूसरी ज्वेलरी मिली। साथ ही साथ 246 मिलियन डॉलर कैश भी उनके घर से बरामद हुआ था।



वाशिंगटन। कोरोनावायरस के बाद मंकीपॉक्स दुनियाभर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अफ्रीका से निकला यह वायरस अब अमेरिका में बढ़ा रूप ले रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका में 30 से ज्यादा बच्चे मंकीपॉक्स से संक्रमित मिले हैं। टेक्सास राज्य स्वास्थ्य सेवा विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में नौ बच्चे वायरस की चपेट में हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 18,989 मंकीपॉक्स और ऑर्थोपॉक्सवायरस के मामले हैं। इस बीच, टेक्सास में मंकीपॉक्स से पीड़ित एक व्यक्ति की पहली मौत की सूचना मिली है। टेक्सास राज्य स्वास्थ्य सेवा विभाग ने (स्थानीय समयानुसार) एक बयान में कहा कि मरीज हैरिस काउंटी में रहने वाला एक वयस्क था।

पूर्व राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे लौटेंगे श्रीलंका, रक्षा अधिकारियों ने दी खबर

स्वदेश लौट सकते हैं। डेली मिरर ने राजपक्षे के करीबी रूस में श्रीलंका के पूर्व राजदूत उदयंगा वीरातुंगा के हवाले से यह खबर दी है। उन्होंने संकेत दिया कि

राजपक्षे वापस थाईलैंड से देश लौट सकते हैं। इससे पहले उन्होंने संकेत दिया था कि 24 अगस्त को स्वदेश लौट सकते हैं। गोतलब है कि गोतबाया राजपक्षे पिछले महीने मालदीव भाग गए थे और उसके बाद वहां से सिंगापुर भाग गए। उन्होंने मंडिकल वीजा पर सिंगापुर में प्रवेश किया और वहां रहने के लिए इस दो बार

बढ़ाया गया। चूंकि इसके बाद उनके वीजा आगे नहीं बढ़ाया जा सका इसलिए राजपक्षे और उनकी पत्नी थाईलैंड के लिए रवाना हुए। थाई सरकार ने उन्हें आश्रय दिया था कि वे वहां 90 दिनों तक रह सकते हैं। हालांकि, राजपक्षे को थाईलैंड में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। फिलहाल, पूर्व राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे अपनी पत्नी लोमा राजपक्षे के साथ बैंकॉक के एक होटल में ठहर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राजपक्षे के नेतृत्व वाली एसएलपीपी द्वारा उनसे अनुरोध किए जाने के बाद राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने उनकी वापसी की व्यवस्था की है। 19 अगस्त को एसएलपीपी के महासचिव सागर करियावासम ने कहा कि राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के साथ हुई बैठक में ये अनुरोध किया गया था।



डिपार्चर गेट नं. 1 व टर्मिनल नंबर 3 के सामने जमा हो गई। ये लोग लुफ्थान्सा की फ्लैगशिप एयरलाइंस के डीसीपी ने बताया कि रात करीब 12 बजे 150 से ज्यादा लोगों की भीड़ एयरपोर्ट के

डिपार्चर गेट नं. 1 व टर्मिनल नंबर 3 के सामने जमा हो गई। ये लोग लुफ्थान्सा की फ्लैगशिप एयरलाइंस के डीसीपी ने बताया कि रात करीब 12 बजे 150 से ज्यादा लोगों की भीड़ एयरपोर्ट के

डिपार्चर गेट नं. 1 व टर्मिनल नंबर 3 के सामने जमा हो गई। ये लोग लुफ्थान्सा की फ्लैगशिप एयरलाइंस के डीसीपी ने बताया कि रात करीब 12 बजे 150 से ज्यादा लोगों की भीड़ एयरपोर्ट के

टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, एशिया कप से बाहर हुए 'सर जडेजा', अक्षर पटेल को किया शामिल

भारत के प्रणॉय जापान ओपन के क्वार्टर फाइनल में हारे



दुबई (एजेंसी)।

भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा चोट के चलते भारतीय टीम से

बाहर हो गए हैं। ऐसे में रवींद्र जडेजा के स्थान पर अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) ने इसकी जानकारी दी।

बीसीसीआई ने बताया अखिल भारतीय वरिष्ठ चयन समिति ने मौजूदा एशिया कप में रवींद्र जडेजा के स्थान पर अक्षर पटेल को नामित किया है। रवींद्र जडेजा के दाहिने घुटने में चोट लगी है और वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। वह फिलहाल बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं।

रटेंडबाय पर थे अक्षर पटेल

आपको बता दें कि एशिया कप के लिए टीम का ऐलान होने पर कुछ खिलाड़ियों को स्टैंडबाय पर रखा गया था।

जिसमें अक्षर पटेल का भी नाम शामिल था। ऐसे में रवींद्र जडेजा के स्थान पर अक्षर पटेल जल्द ही दुबई में टीम से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने अभी तक एशिया कप में दो टीमों के साथ मुकाबला खेला है और दोनों टीमों को मात दी है। हालांकि रवींद्र जडेजा का चोटिल होना टीम के लिए बड़ा झटका है।

जडेजा का नहीं है कोई सानी

एशिया कप के शुरुआती दोनों मुकाबलों में भारतीय टीम ने अच्छे प्रदर्शन किया। जिसमें पाकिस्तान और हांगकांग के खिलाफ मुकाबला शामिल है। पाकिस्तान के खिलाफ रवींद्र जडेजा ने 29 गेंदों में 120 के स्ट्राइक रेट से 35 रन बनाए और उनकी इसी पारी की बदौलत भारतीय टीम के ऊपर से दबाव समाप्त

हुआ और हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। हांगकांग के खिलाफ मुकाबले की बात की जाए तो रवींद्र जडेजा ने 4 ओवर के अपने स्पेल में 15 रन देकर एक विकेट चटकवाया था और तो और उनके शानदार ध्रो ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। दरअसल, रवींद्र जडेजा ने हांगकांग के कप्तान निजाकत खान को रनआउट कर पवेलियन भेजने का काम किया था।

भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), विजय कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, अवेश खान



ओसाका (एजेंसी)।

भारत के एचएस प्रणय जापान ओपन सुपर बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हार के साथ ही बाहर हो गये हैं। प्रणय को चीनी ताइपे के चाउ तिएन चेन के हाथों तीन गेम तक चले मुकाबले में 21-17, 15-21, 22-20 से हराया। इसके साथ ही इस टूर्नामेंट में भारत की सभी उम्मीदें भी समाप्त हो गई हैं। प्रणय और चीनी ताइपे के खिलाड़ी के बीच करीब सवा घंटे तक मुकाबला हुआ। वहीं भारत के अन्य खिलाड़ी पहले ही इस चैंपियनशिप से बाहर हो गये थे।

पिछले कुछ समय से लगातार अच्छे प्रदर्शन कर रहे प्रणय ने इस मैच में जमकर संघर्ष किया। इस भारतीय खिलाड़ी ने पहला गेम हारने के बाद अच्छी वापसी करते हुए तीसरे और निर्णायक गेम में भी अंत तक अपनी संभावनाएं बनाये रखीं। प्रणय ने इस मैच में

पहले गेम से ही दबदबा बनाना शुरू करते हुए एक समय 12-8 की बढ़त हासिल कर ली। चाउ ने हालांकि प्रणय की गलतियों का लाभ उठाते हुए शीघ्र ही 15-14 से बढ़त ले ली। चाउ ने दूसरे गेम में भी 5-4 की मामूली बढ़त से शुरुआत की। प्रणय ने तीसरे और निर्णायक गेम में शुरू में गलतियों की जिससे चाउ ने 6-4 की बढ़त हासिल कर दी। इंटरवल तक ताइपे के खिलाड़ी के पास छह अंक की मजबूत बढ़त थी लेकिन प्रणय ने शानदार क्रॉस कोर्ट लगाकर जल्द ही स्कोर 12-13 कर दिया। प्रणय ने फिर से गलतियों की जिससे चाउ ने 17-14 से बढ़त बना दी। भारतीय खिलाड़ी ने इसके बाद तीन मैच अंक बचाए लेकिन फिर से उनकी सर्विस सही नहीं रही जिससे चाउ को मैच अंक मिला और इस बार उन्होंने उसे हासिल करने में कोई गलती नहीं की।

बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में दो विकेट से हराकर श्रीलंका 'सुपर फोर' में

दुबई (एजेंसी)।

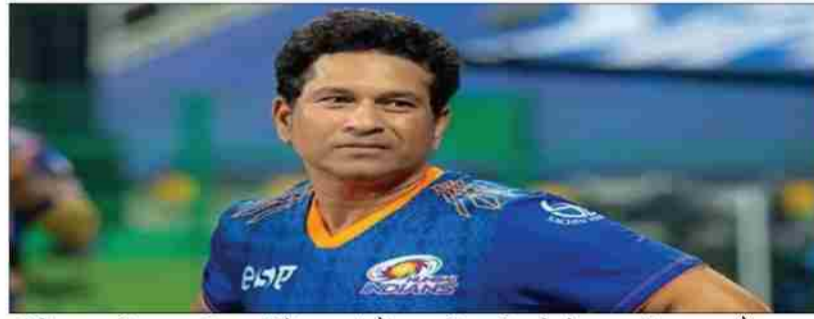
किस्मत के रथ पर सवार कुसल मंडिस की 60 रन की पारी के साथ कप्तान दासुन शनका (45 रन) के साथ पचवें विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी के दम पर श्रीलंका ने एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के रोमांचक मुकाबले में गुरुवार को यहां बांग्लादेश को दो विकेट से शिकस्त देकर 'सुपर फोर' में अपनी जगह पक्की की। दोनों टीमों के लिए करो और मरो के मुकाबले में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 183 रन बनाये। श्रीलंका ने चार गेंद शेष रहते इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। टीम को पदार्पण कर रहे 10वें क्रम के बल्लेबाज अमिथा फर्नांडो ने तीन गेंद में नाबाद 10 रन बनाकर जीत दिला दी। दुबई के मैदान पर यह लक्ष्य का पीछा करते हुए यह सबसे बड़ी जीत है। मंडिस को अपनी पारी के दौरान चार जीवदान मिले। उन्होंने 37 गेंद में चार चौके और तीन छक्के जड़े। शनका ने 33 गेंद की पारी में तीन चौके और दो छक्के लगाये।

श्रीलंका के लिए पदार्पण कर रहे इबादत हुसैन ने चार ओवर में 51 रन देकर तीन विकेट लिये। इससे पहले अफीफ हुसैन (22 गेंद में 39 रन), मेहदी हसन मिराज (26 गेंद में दो चौके और दो छक्के की मदद से 38 रन), महमूदुल्लाह (22 गेंद में 27 रन) और मोसादेक हुसैन की आक्रामक पारियों के दम पर बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सर्वोच्च स्कोर खड़ा किया। मोसादेक हुसैन ने आखिरी ओवरों में नौ गेंद की नाबाद पारी में चार चौकों की मदद से 24 रन बनाकर टीम के स्कोर को 183 के पार पहुंचाया। टीम के लिए कप्तान शाकिब अल हसन ने 22 गेंद में 24 रन का योगदान दिया। वह इस दौरान टी20 (घरेलू, लीग और अंतरराष्ट्रीय) में 6000 रन और 400 विकेट पूरा करने वाले दूसरे क्रिकेटर बने। श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा और चमिका करुणार्त्ते ने दो-दो विकेट लिये। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पशुम निसका और मेडिस ने शुरुआती पांच ओवर में 44 रन जोड़कर श्रीलंका को शानदार शुरुआत दिलायी।

सचिन करेंगे रोड सेफ्टी विश्व सीरीज के दूसरे सत्र में इंडिया लीजेंड्स की कप्तानी

मुंबई (एजेंसी)।

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर रोड सेफ्टी (सड़क सुरक्षा) विश्व सीरीज के दूसरे सत्र की कप्तानी करेंगे। वहीं पहले सत्र में भी सचिन ने इंडिया लीजेंड्स की कप्तानी की थी। सचिन के साथ इस लीग में आक्रामक बल्लेबाज युवराज सिंह, इफ्रान पठान, यूसुफ पठान, राहुल शर्मा जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। दूसरे सत्र का आयोजन 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 22 दिन तक अलग अलग स्थानों पर होगा। इस टूर्नामेंट का पहला मैच कानपुर में खेला। वहीं दोनों सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले रायपुर में खेले जाएंगे। वहीं इसके अलावा इंदौर और देहरादून में भी मुकाबले होंगे। इस बार इस टूर्नामेंट में इंडिया लीजेंड्स, श्रीलंका लीजेंड्स, ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स, बांग्लादेश लीजेंड्स, वेस्टइंडीज



लीजेंड्स, दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स, इंग्लैंड लीजेंड्स और न्यूजीलैंड लीजेंड्स सहित कुल मिलाकर आठ टीमों का भाग ले रही है।

इस लीग का मुख्य लक्ष्य देश और विश्व भर में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस सीरीज को लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि रोड सेफ्टी विश्व सीरीज सामाजिक बदलाव में अहम भूमिका निभाने के साथ ही सड़क और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों का रुख बदलने के लिए एक आदर्श मंच साबित होगी।" वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, "रोड सेफ्टी विश्व सीरीज क्रिकेट के जरिये सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और लोग यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित होंगे।"

डायमंड लीग में स्वर्ण जीतने अभ्यास कर रहे नीरज चोपड़ा

नई दिल्ली (एजेंसी)।

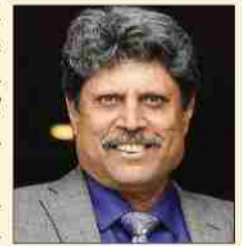
भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का लक्ष्य अब 7 से 8 सितंबर के बीच ज्यूरिख में होने वाले प्रतिष्ठित डायमंड लीग में स्वर्ण जीतना है। विश्व रैंकिंग में दूसरे नंबर के खिलाड़ी नीरज इसके लिए अभ्यास में लगे हुए हैं। इस खिलाड़ी ने डायमंड लीग में स्वर्ण जीतने के साथ ही

फाइनल में जगह बनायी थी। इस साल जुलाई महीने में नीरज ने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता था पर चोट लगने के कारण वह बर्मिंघम में हुए राष्ट्रमण्डल खेलों में भाग नहीं ले पाये थे। अब नीरज पूरी तरह फिट होकर अभ्यास में लग गये हैं। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें वह कड़ा अभ्यास करते हुए दिख रहे हैं। उनका ध्यान अभ्यास के साथ ही फिटनेस बनाये रखने

पर भी है। नीरज ने अब तक 90 मीटर तक भाला नहीं फेंका है। इस बार उनका लक्ष्य इस आंकड़े को पार करना होगा। ऐसे में वह डायमंड लीग फाइनल में पूरा जोर लगा देंगे। लुसाने में शीर्ष पर रहने के साथ ही नीरज ने दो इवेंट में 15 अंकों के साथ ही फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था। नीरज से पहले चक्रा फेंक एथलीट विकास गौड़ा ही एकमात्र भारतीय हैं जो डायमंड लीग प्रतियोगिता में शीर्ष तीन में रहे थे।

अपनी फिटनेस का ध्यान रखें पंड्या: कपिल

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को तारीफ की है पर इसके साथ ही कहा कि उन्हें अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना होगा। कपिल ने हा कि हार्दिक पंड्या और रवींद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ियों का होना टीम के लिए हमेशा ही लाभदायक होता है। इस महान ऑलराउंडर ने कहा, यहीं से टीम को लाभ मिलता है। साथ ही कहा कि भारतीय टीम के पास हार्दिक और जडेजा जैसे ऑलराउंडर हैं जो अपने ओवर फेंक सकते हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। कोई भी ऑलराउंडर टीम के लिए अहम होता है। हार्दिक ने हमें अपने खेल से हमें गौरव का अनुभव कराया है पर इसके साथ ही उन्हें अपनी देखभाल भी करनी होगी क्योंकि जब एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी चोटिल होता है तो पूरी टीम पर प्रभाव पड़ता है। उनकी योग्यता पर किसी को भी संदेह नहीं हो सकता है पर मुझे उनकी फिटनेस की चिंता होती है। साथ ही कहा कि अगर हार्दिक चोटिल हो जाते हैं तो यह निश्चित रूप से टीम के पूरे ढांचे को ही घसट कर देगा। पंड्या ने पाक के खिलाफ मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की थी।



पूर्व गोलकीपर कल्याण एआईएफएफ के नये अध्यक्ष होंगे, भूटिया हारे

हारिस उपाध्यक्ष, अजय कोषाध्यक्ष पद के लिए जीते

नई दिल्ली (एजेंसी)।

पूर्व गोलकीपर कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के नये अध्यक्ष होंगे। कल्याण ने अध्यक्ष पद की दौड़ में पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया को हराया है। फुटबॉल महासंघ के इतिहास में यह पहली बार है जब कोई खिलाड़ी अध्यक्ष बना है। आज हुए अध्यक्ष पद के चुनाव में कल्याण ने 33-1 से जीत दर्ज की। मोहन बागान और इस्ट बंगाल के इस पूर्व खिलाड़ी की जीत पहले ही तय हो गयी थी। इसका कारण यह था कि पूर्व कप्तान भूटिया का राज्य सभों के प्रतिनिधियों के 34 सदस्यीय निर्वाचक मंडल से अधिक समर्थन नहीं मिला था। यह तक कि दिग्गज खिलाड़ी भूटिया का नामांकन पत्र भारते समय उनके साथ राज्य संघ का कोई भी प्रतिनिधि प्रस्तावक या अनुमोदक के तौर पर नहीं आया था। अध्यक्ष पद पर पहुंचे कल्याण ने

अधिकतर वलब स्तर पर ही खेला है। वह कुछ एक बार ही सीनियर टीम का हिस्सा रहे थे। उन्होंने हालांकि कम आयु वर्ग के टूर्नामेंट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भूटिया ने भी कल्याण के साथ एक समय इस्ट बंगाल टीम में खेला था। वहीं कर्नाटक फुटबॉल संघ के अध्यक्ष एनए हारिस उपाध्यक्ष पद के लिए जीते हैं। उन्होंने राजस्थान फुटबॉल संघ के प्रमुख मानवेंद्र सिंह को 29-5 से हराया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कप्तान अजय कोषाध्यक्ष पद के लिए विजयी रहे हैं। अजय ने ओडिशा प्रदेश के गोपालकृष्णा कोसाराजू को 32-1 से हराया था।

गौरतलब है कि कोसाराजू ने अध्यक्ष पद के लिए भूटिया के नाम का प्रस्ताव रखा था जबकि मानवेंद्र ने उसका समर्थन किया था। कार्यकारिणी के 14 सदस्यों के लिए इतने ही उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था और

इन सभी का चयन निर्विरोध हुआ है। गया। विश्व फुटबॉल की नई कार्यकारी समिति के सदस्य हैं। जीपी शर्मा, अविजीत पॉल, पी अनिलकुमार, वलंका नताशा अलेमाओ, मालोजी राजे छत्रपति, मेनला एथेनपा, मोहन लाल, आरिफ अली, के नीबी सेखोज, लालनधिंरलोवा हमर, दीपक शर्मा, विजय बाली और संयद इतियाज हुसैन शामिल किये गये हैं। वहीं भारतीय फुटबॉल संघ के प्रमुख अली और क्लाइमैक्स लॉरेंस खिलाड़ियों के प्रतिनिधि के रूप में कार्यकारिणी में रहेंगे।



वहीं हार से निराश भूटिया ने कहा, "मैं भारतीय फुटबॉल की बेहतरी के लिए आगे भी काम करता रहूंगा। विजयी रहे कल्याण को बधाई। मुझे उम्मीद है कि वह अपने काम से भारतीय फुटबॉल को आगे लेकर जाएंगे।" उन्होंने कहा, "भारतीय फुटबॉल निलंबित कर दिया था।

दिलचस्प है नागिन डांस का इतिहास, बांग्लादेश-श्रीलंका के मैच में खिलाड़ी खूब करते हैं इसका इस्तेमाल

नयी दिल्ली (एजेंसी)।

गुरुवार को एशिया कप में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेले गए मुकाबले का दिलचस्प अंत हुआ। रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को श्रीलंका ने हरा दिया और टॉप 4 में जगह भी बना ली। लेकिन इस मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में श्रीलंका के खिलाड़ी चमिका करुणार्त्ते नागिन डांस करते नजर आ रहे हैं। हालांकि यह पहला मौका नहीं है, जब दोनों देशों के बीच हुए मुकाबले में नागिन डांस देखने को मिला है। इससे पहले भी कई मौके आए हैं, जब दोनों देशों के खिलाड़ी एक दूसरे के प्रति नागिन डांस करते दिखे हैं। हालांकि, इसकी शुरुआत कब हुई यह हम आपको बताते हैं। कहानी की शुरुआत 2016 में हुई थी। बांग्लादेश के बाएं हाथ के स्पिनर नजमुल

इस्लाम अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और बांग्लादेश लीग में खेल रहे थे। नजमुल अचानक अपना हाथ ऊपर करके नागिन डांस करने लगे। बाद में कप्तान डेरेन सैमी भी हरकत में आए। इस पर नजमुल ने 2017 में कहा था कि खेल के दौरान नागिन डांस करने की कोशिश की लेकिन डेरेन सैमी डरने का नाटक किया। तभी से यह शुरू हुआ और आज तक जारी है। इसके बाद से यह मेरा ट्रेडमार्क बन गया।

बांग्लादेश-श्रीलंका के मुकाबले में कैसे हुई हंटी

नजमुल ने अपने अधिकतम खेलों में नागिन डांस किया है। बीपीएल के दौरान भी उन्होंने काफी बार ऐसा करने की कोशिश की है। हालांकि, 2018 में बांग्लादेश के लिए नजमुल ने टी20 में पदार्पण किया। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला था। उन्होंने चार विकेट चटकाए। इसमें दनुष्का गुणथिलका का

भी विकेट शामिल था। दनुष्का स्टंप आउट हुए थे जिसके बाद मुशफिकुर रहम ने नागिन डांस किया था। सभी बांग्लादेश खिलाड़ी ड्रेंड में शामिल हो गए और नागिन डांस करने की कोशिश करने लगे।

श्रीलंका ने किया पलटवार

टी20 मैच में श्रीलंका की ओर से इस नागिन डांस का पलटवार किया गया। श्रीलंका ने यह सीरीज जीत ली थी और गुणथिलका ने दूसरे मैच के 18वें ओवर में 2 विकेट चटकाने में कामयाब रहे। इसके बाद उन्होंने पलटवार में नागिन डांस करने की कोशिश की। बताया जाता है कि बांग्लादेश के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहम ने इसे नाटिस किया था। तब से लगातार दोनों देशों के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में बार-बार पलटवार के तौर पर किया जाता रहा है।



नागिन डांस बना ताने का प्रतीक

धीरे-धीरे यह नागिन डांस दोनों देशों के खिलाड़ियों के लिए ताने का प्रतीक बन गया। 2018 में निदहास ट्रॉफी के दौरान बांग्लादेश की टीम श्रीलंका दौरे पर थी। इस ट्रॉफी में भारत भी हिस्सा ले रहा था। बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका ने अपना पहला मुकाबला जीता जिसमें उसने 215 रनों के लक्ष्य का पीछा किया।

मुशफिकुर रहम ने 35 गेंदों में 72 रनों की पारी खेली। इसके बाद उन्होंने नागिन डांस किया था। इस घटना पर बांग्लादेश के सीनियर बल्लेबाज तमीम इकबाल ने कहा था कि इसमें मुशफिकुर रहम का कोई दोष नहीं। श्रीलंका की टीम ने बांग्लादेश दौरे के दौरान ऐसा किया था। मुझे लगता है कि दनुष्का ने ही पहले किया था। रहम ने उसे नाटिस किया था और यह उसके दिमाग में था।

अपने ही रैकेट से चोटिल हो गए राफेल नडाल, रोकना पड़ा मैच

न्यूयॉर्क।

राफेल नडाल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर के मैच के दौरान अपनी ही गलती से नाक पर चोट लगा बैठे जिसके कारण खून बहने लगा गया था। बाईस बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल ने फैब्रियो फोगनिनी पर 2-6, 6-4, 6-2, 6-1 से जीत दर्ज की। इस बीच चौथे सेट में गलती से उन्होंने एक शॉट बचाने के प्रयास में अपने ही रैकेट से नाक पर चोट लगा दी। इससे उनकी नाक से खून बहने लगा गया था। आर्थर एस स्टेडियम में इस घटना से अजीबोगरीब स्थिति बन गई और लगभग पांच मिनट तक खेल रुका रहा। नडाल ने तुरंत ही दोनों हाथों से अपना मुंह ढक दिया और मैच के बाद इस घटना को लेकर मजाकिया अंदाज में बात भी की। नडाल से पूछा गया क्या इससे पहले भी उनके साथ ऐसा घटना घटी थी, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "गोल्फ कोर्स में ऐसा हुआ था लेकिन टेनिस रैकेट से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। शुरू में मुझे थोड़ा चकरा जैसा आया। तब हल्का दर्द हो रहा था।"



पीएम मोदी ने देश को सौंपा आईएनएस विक्रान्त, बोले- भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का एक उदाहरण

नई दिल्ली, 02 सितम्बर (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन में देश के पहले स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रान्त को भारतीय नौसेना को समर्पित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यहां भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रान्त का जलावतरण किया। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की फेहरिस्त में शामिल हो गया है, जिनके पास ऐसे बड़े युद्धपोतों के निर्माण की घरेलू क्षमताएं हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने यहां कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में स्वदेशी निर्मित जहाज को नौसेना के बेड़े में शामिल किया। इस जहाज का नाम नौसेना के एक पूर्व जहाज विक्रान्त के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभायी थी। कुल 262 मीटर लंबा तथा 62 मीटर चौड़ा यह जहाज 28 समुद्री मील से लेकर 7500 समुद्री मील की दूरी तय कर सकता है। 20,000 करोड़ रुपये की लागत से बना यह विमान वाहक जहाज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह देश में बने एडवॉन्सड लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) के अलावा मिग-29के लड़ाकू विमान सहित 30 विमान संचालित करने की क्षमता रखता है।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रान्त का जलावतरण करते हुए कहा, आईएनएस विक्रान्त भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। आईएनएस विक्रान्त के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है, जो स्वदेशी स्तर पर विमानवाहक पोत बना सकते हैं।

मोदी ने कहा, विक्रान्त विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रान्त विशिष्ट है, विक्रान्त विशेष भी है। विक्रान्त केवल एक युद्धपोत नहीं है। यह 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

सीएसएल पर आईएनएस विक्रान्त के जलावतरण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरी कुमार सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए।

मोदी ने कहा, यदि लक्ष्य दूरत हैं, यात्राएं दिगंत हैं, समंदर और चुनौतियाँ अनंत हैं तो भारत का उत्तर है विक्रान्त। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रान्त। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रान्त।

महिला शक्ति पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, विक्रान्त जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा, तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी नैनात रहेंगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति, ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है।

वोकल फॉर लोकल के मंत्र को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, बूंद-बूंद जल से जैसे विराट समंदर बन जाता है। वैसे ही भारत का एक-एक नागरिक वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जीना प्रारंभ कर देगा, तो देश को आत्मनिर्भर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा।

नौसेना का बजट बढ़ाने पर मोदी ने कहा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र और हिंद महासागर में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया है, लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्राथमिकता है। इसलिए हम नौसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी क्षमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह आईएनएस विक्रान्त को मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी को समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया, जो दुश्मनों की नौदल उड़ाकर रखती थी। जब अंग्रेज भारत आए, तो वे भारतीय जहाजों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से चबराए रहते थे। इसलिए उन्होंने भारत के समुद्री सामर्थ्य की कमी तोड़ने का फैसला

लिया। इतिहास गवाह है कि कैसे उस समय ब्रिटिश संसद में कानून बनाकर भारतीय जहाजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे।

प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के नए निशान (ध्वज) का अनावरण करते हुए कहा कि भारत ने औपनिवेशिक अतीत को त्याग दिया है। उन्होंने कहा, आज दो सितंबर, 2022 की ऐतिहासिक तारीख को, इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने, गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है।

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जहाजरानी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनारई विजयन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जगह केंद्र विपक्षी सरकारों को पटरी से उतार रहा है: कांग्रेस

नई दिल्ली, 02 सितम्बर (एजेन्सी)। कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उस पर अर्थव्यवस्था के अकुशल प्रबंधन और इस बारे में उसकी अनभिज्ञता की वजह से भारत की विकास गाथा को पीछे धकेलने का आरोप लगाया और कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जगह वह विपक्षी सरकारों को सत्ता की पटरी से उतारने का प्रयास कर रही है। प्रमुख विपक्षी पार्टी ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या भारत को पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने, किसानों की आय दोगुनी करने और 2022 तक सभी को पक्का मकान देने के अपने वादे से सरकार पीछे हटेगी?

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, अब यह स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था के अकुशल प्रबंधन, कोई ध्यान न देने और उसकी अनभिज्ञता की वजह से भारत के विकास की कहानी पीछे छूट रही है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले तीन सालों में तीन प्रतिशत का विकास देखा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को 'तबाह' करने का आरोप लगाया। वल्लभ ने कहा, 'यहां तक कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2023 में विकास दर के 7.5 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत होने का अनुमान जताया है।'

उन्होंने कहा कि अन्य वैश्विक बैंकों और रेटिंग एजेंसियों ने भी इसी प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने सवाल किया, सरकार की अपेक्षा के अनुरूप भारत कब पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा? क्या सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने और सभी पात्र शहरी परिवारों को 2022 तक पक्का मकान देने के वादे से पीछे हटने का इरादा रखती है? कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, वैश्विक स्तर पर आ रहे बदलावों और भारत की सुस्त वृद्धि दर के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की आवश्यकता है लेकिन वित्त मंत्री इन चिंताजनक आंकड़ों से बेपरवाह हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक रूपांतरण तैयार करने की बजाय सरकार का पूरा जोर विपक्ष शासित सरकारों को अस्थिर करने पर है।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर पहले भी आरोप लगाती रही है कि वह विपक्ष शासित राज्यों को गिराने के प्रयास में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वल्लभ ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने के लिए किसी को 'मन की बात' की जरूरत नहीं है क्योंकि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 79.70 पर पहुंच गया है और सीएनआई के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2022 में बेरोजगारी की दर 8.28 प्रतिशत बढ़ गई है। आधिकारिक आंकड़ों में बुधवार को कहा गया कि भारत



दुनिया में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 13.5 प्रतिशत रही जो पिछले एक साल में सबसे अधिक है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 13.5 प्रतिशत रही। इससे पिछले वित्त वर्ष (2021-22) की अप्रैल-जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 20.1 प्रतिशत रही थी। जनवरी-मार्च, 2022 में 4.09 प्रतिशत रही थी। वल्लभ ने इन आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार की हैदलाइन प्रबंधन मशीनीरी की ओर से कुछ आंकड़ों से जुड़े कुछ बिन्दुओं को आगे बढ़ाया जाता है लेकिन सच्चाई तब सामने आती है जब जब हम गहराई से आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। उन्होंने कहा, हमारी आर्थिक स्थिति की वास्तविकता क्या है, यह तभी पता चलेगा जब हम इसकी तुलना कोविड से पूर्व की स्थिति से करेंगे।

छत्तीसगढ़ में भी जल्द होगी ईडी-आयकर की छापेमारी, सीएम बघेल का दावा

रायपुर, 02 सितम्बर (एजेन्सी)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कहा कि उनके राज्य में भी जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर (आईटी) विभाग के छापे पड़ते नजर आएंगे, क्योंकि झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक रायपुर के पास एक रिसॉर्ट में ठहरे हुए हैं।



राजधानी रायपुर में हेलीपैड पर पत्रकारों से बात करते हुए सीएम बघेल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के घटक दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायकों को लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए रायपुर के बाहरी क्षेत्र में एक रिसॉर्ट में रखा गया है।

पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और कुछ देर के लिए हिरासत में लिया।

इन भाजयुमो कार्यकर्ताओं के हाथों में पोस्टर थे जिन पर लिखा था, "अंकित हम शर्मिदा हैं, तेरे कातिल जिदा है।" झारखंड के दुमका जिले में एक व्यक्ति ने बारहवीं कक्षा की छात्रा अंकिता को कथित रूप से आग लगा दी थी और उस छात्रा ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।

भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा, "झारखंड में अराजकता है तथा कानून व्यवस्था चरमरा गई है। लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन सत्तारूढ़ संग्राम के विधायक रायपुर में पिकनिक मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने राज्य में मध्वनिषेध लागू करने का वादा किया था, लेकिन वह झारखंड के विधायकों को शराब परोस रही है।

एक अधिकारी ने बताया कि भाजयुमो के 41 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और उन्हें बस से राखी थाने ले जाया गया, जहां उन्हें बिना शर्त छोड़ दिया गया।

बता दें कि, झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन सरकार ने मंगलवार को अपने 32 विधायकों को रायपुर पहुंचा दिया था। माना जा रहा है कि उसने राज्य में वर्तमान राजनीतिक संकट के मद्देनजर विपक्षी भाजपा द्वारा विधायकों की कथित खरीद फरोख्त के प्रयासों को विफल करने के लिए यह कदम उठाया है।

शिंदे और उद्धव में अब दशहरे पर होगी महाभारत, ग्राउंड के लिए दोनों मैदान में

मुंबई, 02 सितम्बर (एजेन्सी)। इस साल दशहरे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में महाभारत देखने को मिल सकती है। कारण है- एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच शिवसेना को लेकर चल रही वर्चस्व की जंग। दरअसल, मुंबई नगर निकाय के मुताबिक, दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क की बुकिंग के लिए उद्धव ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे दोनों समूहों की तरफ से आवेदन आए हैं। दशहरा रैली शिवसेना के लिए हमेशा से ही बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। बालासाहेब ठाकरे के दौर से ही इस पार्क में हर साल दशहरा रैली होती रही है। जिसमें प्रदेश भर के शिवसैनिकों का जमावड़ा होता है। ऐसे में दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क की बुकिंग करके एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के बीच शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है।

मुंबई के नगर निकाय ने शुक्रवार को कहा कि उसे उद्धव ठाकरे और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुटों से दशहरा रैली के लिए विशाल शिवाजी पार्क को बुक करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह रैली हमेशा से शिवसेना के राजनीतिक कैलेंडर के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा है। यह सिलसिला बालासाहेब द्वारा शुरू किया गया और अब उद्धव ठाकरे इसे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन, जून में एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद सेना में विभाजन के कारण शिवसेना दो खेमों में बंट गई है। शिंदे महाराष्ट्र के मुखिया हैं और प्रदेश की सत्ता उनके हाथ में है। शिंदे कई मौकों पर खुद को असली शिवसैनिक भी कह चुके हैं।

इस बार दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क में महाभारत तय है। रैली के लिए शिंदे और उद्धव दोनों गुटों ने अपनी दावेदारी पेश की है। नगर निकाय के मुताबिक, पहला

आवेदन 22 अगस्त को शिवसेना के ठाकरे धड़े का था और दूसरा गणेश उत्सव से ठीक पहले शिंदे समूह की तरफ से आया। कुछ दशक पहले जाएं तो शिवाजी पार्क पर पहली दशहरा रैली 1966 में आयोजित की गई थी और इसे शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे ने संवोधित किया था। बालासाहेब अपनी बेबाकी और तीखे भाषण के लिए जाने जाते थे। इस कार्यक्रम में उनको सुनने के लिए राज्यभर से शिवसैनिक बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे।

गौरतलब है कि इससे पहले, उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनकी पार्टी पहले की तरह शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करेगी, जबकि उनके बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया था कि रैली के लिए पार्टी के आवेदन को अधिकारियों से बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

ईडी की पूछताछ के बाद केंद्र पर बरसे अभिषेक बनर्जी, मोदी सरकार को दे डाली खुली चुनौती

कोलकाता, 02 सितम्बर (एजेन्सी)। कथित कोयला चोरी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुक्रवार को सात घंटे तक पूछताछ किए जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी कि अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो वह उन्हें सलाखों के पीछे डाल दें। बनर्जी ने कहा कि वह धमकियों और केंद्रीय एजेंसी द्वारा समन जारी किए जाने से नहीं डरेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करने का संकल्प लिया।

बनर्जी ने कहा, यदि जरूरत पड़े, तो मैं 30 बार पूछताछ का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं भाजपा के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। मैंने राष्ट्रध्वज के मामले पर उनके (शाह के) बेटे पर निशाना साधा, तो इसका मतलब



यह नहीं है कि मुझे डराने के लिए ईडी और सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) का इस्तेमाल किया जा सकता है।

केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह एक वीडियो क्लिप में भारत द्वारा पाकिस्तान को एक रोमांचक क्रिकेट मैच में हराने के बाद राष्ट्रीय ध्वज लहराने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए प्रतीत हुए। दुबई में एशिया कप मुकाबले के 28 अगस्त

को हुए इस मैच की क्लिप ने विवाद खड़ा कर दिया।

टीएमसी महासचिव ने कहा, मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि वह साबित करें कि मैंने कुछ गलत किया है और मुझे सलाखों के पीछे डाल दें। तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव ने आरोप लगाया कि देश के गृह मंत्री का केवल एक ही काम है - विपक्षी दलों की निर्वाचित राज्य सरकारों को गिराने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त करना।

अरुणाचल में सभी विधायकों के बाद मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक बीजेपी में शामिल

इम्फाल, 02 सितम्बर (एजेन्सी)। अरुणाचल प्रदेश के बाद अब मणिपुर में भी जनता दल युनाइटेड को तगड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को जेडीयू के छह में से पांच विधायक राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए। इसी के साथ प्रदेश की 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या बढ़कर अब 37 पहुंच गई है। विधायकों की ओर से यह कदम पिछले महीने बिहार में बीजेपी और जेडीयू के रास्ते अलग-अलग होने के बाद उठाया गया है। चर्चा थी की बिहार में अलग होने के बाद जेडीयू मणिपुर में एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने की योजना बना रही है।

विधानसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष टीएच सत्यन्रत सिंह ने जद (यू) के 5 विधायकों - केएच

जॉयकिशन, एन सनाते, मोहम्मद अख्बउद्दीन, पूर्व पुलिस महानिदेशक ए एम खाउटे और थांगजाम अरुणकुमार के बीजेपी में विलय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

मणिपुर विधानसभा के सचिव के मेघजीत सिंह द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अध्यक्ष ने संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत जदयू के पांच विधायकों के बीजेपी में विलय को स्वीकार करते हुए खुशी जताई है। जदयू ने इस साल मार्च में विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से छह ने जीत दर्ज की थी।

पांच विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद लिलोंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर 60 सदस्यों के सदन में जद(यू) के अकेले विधायक बच गए हैं। जेडी(यू) मणिपुर राज्य इकाई के अध्यक्ष केश

बीरेन सिंह ने कुछ दिन पहले इम्फाल में कहा था कि पार्टी ने पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से अलग होने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। एन बीरेन ने यह भी कहा था कि वो 3 और 4 सितंबर को पटना में होने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे।

इस साल फरवरी-मार्च में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में जेडी(यू) तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पहले नंबर पर बीजेपी थी जिसके खाते में 32 सीटें आई थी, दूसरे नंबर पर नेशनल पीपुल्स पार्टी जिसने 7 सीटें जीतीं। परिणाम के बाद जेडी(यू) ने पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करने और लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया था।

आईएनएस विक्रान्त देश की समुद्री सुरक्षा के लिए अहम कदम : राहुल गांधी

नई दिल्ली, 02 सितम्बर (एजेन्सी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत के लिए शुक्रवार को भारतीय नौसेना, नौसेना डिजाइन ब्यूरो और कोचीन शिपयार्ड को बधाई दी और इस पोत को बेड़े में शामिल किए जाने को देश की समुद्री सुरक्षा के लिए एक अहम कदम बताया।

राहुल ने ट्विटर पर कहा, भारतीय नौसेना, नौसेना डिजाइन ब्यूरो और कोचीन शिपयार्ड को कई वर्षों की कड़ी मेहनत के लिए बहुत-बहुत बधाई, जिससे आईएनएस विक्रान्त का सपना साकार हुआ। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत, आईएनएस विक्रान्त भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक अहम कदम है। उन्होंने आईएनएस विक्रान्त की एक तस्वीर



भी साझा की। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रान्त का शुक्रवार को जलावतरण किया गया। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया जिनके पास ऐसे बड़े युद्धपोतों के निर्माण की घरेलू क्षमताएं हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में एक समारोह में स्वदेश में निर्मित पोत को नौसेना के बेड़े में शामिल किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने आईएनएस विक्रान्त को नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने के मौके पर एक पट्टिका का अनावरण किया। इस पोत का नाम एक पूर्ववर्ती पोत के नाम पर रखा गया है जिसने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

इस नए पोते के साथ ही भारत अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसे बड़े युद्धपोतों के निर्माण की घरेलू क्षमताएं हैं।